राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

समय दर्शन

रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

ESTD : Since 2011

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

वर्ष 14, अंक 243 पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये दुर्ग, बुधवार 02 जुलाई 2025 www.samaydarshan.in

नई खेल नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

2047 तक भारत को शीर्ष-पांच खेल राष्ट्र बनाना लक्ष्य : अश्विनी वैष्णव

नईदिल्ली (एजेंसी)। केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार (01 जुलाई, 2025) को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, खेल से जुड़ी खेलो भारत नीति, रिसर्च एंड डेवलेपमेंट के अलावा तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे को चार लेन का बनाने के लिए मंजूरी दी। कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इसका कुल बजट: 99,446 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देना और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 की जगह लेती है, साथ ही भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के

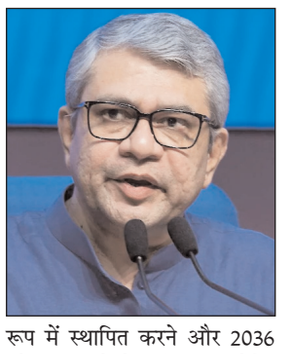

रूप में स्थापित करने और 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप पेश करती है। भारत के रिसर्च एंड डेवलेपमेंट के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दे दी है। आरडीआई योजना का उद्देश्य आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है। यह योजना निजी क्षेत्र के वित्तपोषण में बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है और नवाचार को सुविधाजनक बनाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों को विकास और जोखिम पूंजी प्रदान करने का प्रयास करती है। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन निर्माण को मंजूरी दी। खंड की कुल लंबाई 46.7 किमी है और परियोजना लागत 1,853 करोड़ रुपये है। दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

मौजूदा समय में, मदुरै, परमकुडी, रामनाथपुरम, मंडपम, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच संपर्क मौजूदा 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 87 (एनएच-87) और संबंधित राज्य राजमार्गों पर निर्भर है। जिस वजह से इस राजमार्ग पर भीड़भाड़ रहती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना- सरकार ने मंगलवार को रोजगार सृजन, कौशल बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाको मंजूरी दी है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम

पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू की....

नईदिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 75 साल के इतिहास में पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू की है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक पदों पर नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नीति 23 जून 2025 को लागू हुई। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक कामकाज में बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि जजों पर आरक्षण लागू नहीं होगा और सिर्फ रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट सहायक, चैंबर अटेंडेंट आदि पदों पर आरक्षण लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ही क्यों अपवाद रहे?- आरक्षण लागू करने को लेकर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अगर सभी सरकारी संस्थानों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में आरक्षण नीति लागू है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों अपवाद रखा जाए? उन्होंने कहा कि हमारे मूल्य हमारे एक्शन का आईना होना चाहिए। 24 जून को जारी सर्कुलर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति (एससी) के कर्मचारियों को 15 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

आपराधिक कानून पर बोले शाह

देश में कही भी हो एफआईआर 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा..

नईदिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे। आज इन तीन नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि इस प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन में अधिकतम तीन वर्ष लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी समस्या न्याय प्राप्त करने के लिए समयसीमा का अभाव है। शाह ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज करें, आपको 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने क्रमश: औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। नए कानून 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए। गृह मंत्री ने तीनों कानूनों को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार करार दिया और कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से यह

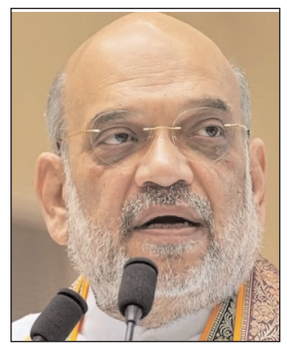

सुनिश्चित होगा कि कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद सजा से बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि न्याय निश्चित रूप से तय समय के भीतर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार, आपकी चुनी हुई सरकार ने आपके लिए कानून बनाए हैं । और यह आपके सभी अधिकारों की रक्षा करेगी। 1 जुलाई, 2024 से, सभी नई एफआईआर बीएनएस के तहत दर्ज की गईं। हालांकि, पहले दर्ज किए गए मामलों को उनके अंतिम निपटारे तक पुराने कानूनों के तहत ही चलाया जाता रहा। नए कानून आधुनिक न्याय प्रणाली लेकर आए, जिसमें जीरो एफआईआर, ऑनलाइन पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल हैं।

एंटी-एजिंग दवाएं बनीं मौत की वजह शेफाली जरीवाला केस में बड़ा खुलासा

मुंबई । अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में पुलिस जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि शेफाली पिछले सात से आठ सालों से नियमित रूप से एंटी-एजिंग दवाओं का सेवन कर रही थीं। 27 जून को उनके घर में पूजा का आयोजन था, जिसके कारण शेफाली व्रत पर थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसी दिन दोपहर में एंटी-एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया था। यह दवाएं उन्हें वर्षों पहले एक डॉक्टर की सलाह पर दी गई थीं, और तब से वह हर महीने यह ट्रीटमेंट लेती आ रही थीं।पुलिस को इस बात का संदेह है कि उनकी अचानक मृत्यु का एक बड़ा कारण यह दवाएं भी हो सकती हैं। जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट हुआ। घटना के समय रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच शेफाली की तबीयत अचानक बिगड़ी, उनका शरीर कांपने लगा और वह बेहोश होकर गिर गईं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घटना के वक्त घर पर शेफाली के पति पराग, मां और कुछ अन्य सदस्य मौजूद थे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

"मौसम के जोखिमों से हमारे मेहनती किसान भाई–बहनों के हितों को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है।"
– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

बेमिसाल खेती की मिसाल बनाओ

फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियाँ

- 23+ करोड़ किसान भाई-बहनों को अब तक मिला फसल बीमा का लाभ
- ₹1.75+ लाख करोड़ के दावों का भुगतान किसानों को किया
- 78+ करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्राप्त
- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल द्वारा पारदर्शी एवं त्वरित दावा भुगतान

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025

फसल बीमा सप्ताह 1-7 जुलाई, 2025 पीएमएफबीवाई

देशव्यापी हेल्पलाइन 14447

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बीमा भागीदार AIC Bajaj Allianz Chola MS Future Generali HDFC ERGO ICICI Lombard IFFCO-TOKIO Kshema Oriental Insurance Reliance General Insurance SBI General Tata AIG Universal Sompo General Insurance

अपनी फसलों को आज ही बीमित करने के लिए संपर्क करें

जनसेवा केंद्र | क्रॉप इंश्योरेंस ऐप https://play.google.com | पोस्ट ऑफिस | बैंक शाखा

@PMFBY

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें

संक्षिप्त समाचार

नगर पंचायत पाटन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 41 हितग्राहियों को भवन स्वीकृत पत्र वितरित किए

पाटन : नगर पंचायत पाटन अध्यक्ष योगेश निक्की भाले द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नगर पंचायत पाटन के वार्ड 1 से 15 वार्ड के कुल 41 पात्र हितग्राहियो को भवन स्वीकृति पत्र वितरित किए गए विदित हो कि छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार द्वारा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वीकृति दी थी इसी कड़ी में पाटन नगर के हितग्राहियों को भी लम्बे समय से इंतजार था एवं उसे आज स्वीकृति पत्र दिया गया जिससे आवास निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किए जा सकेंगे प्रमुख रूप से नगर पंचायत पाटन सीएमओ हेमंत वर्मा,इंजीनियर अर्जुन निर्मल नगर पंचायत उपाध्यक्ष निशा सोनी, सभापति केवल देवांगन,सभापति जितेन्द्र निर्मलकर,पार्षद चंद्रप्रकाश देवांगन,पार्षद अन्नपूर्णा पटेल सहित प्रधानमंत्री आवास योजना आर्किटेक वासुदेव देवांगन,किशोर वर्मा सहित हितग्राही जन उपस्थित थे।

बीमा राशि न मिलने से परेशान किसानों ने जताई पीड़ा, जगजीत सिंह भाटिया से की मुलाकात

छुरिया। क्षेत्र के सैकड़ों किसान इन दिनों रबी फसल की बीमा राशि न मिलने से परेशान हैं। ग्राम खोभा, शिकारी महका, कल्लूटोला, बनियाटोला, मगरधोखरा और मरकाकसा के किसानों ने इस समस्या को लेकर शुक्रवार को भाजयुमो के पूर्व प्रदेश मंत्री जगजीत सिंह भाटिया से मुलाकात की और उन्हें हस्तलिखित आवेदन सौंपा। किसानों ने बताया कि वर्ष 2024-25 की रबी फसल के बीमा की राशि अब तक नहीं मिली है। समय पर राशि न मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की परेशानी सुनकर श्री भाटिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम से दूरभाष पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री को न सिर्फ बीमा राशि संबंधी समस्या बताई, बल्कि खाद की किल्लत की भी जानकारी दी।

एक सप्ताह में समस्या समाधान का मिला आश्वासन

श्री भाटिया के प्रयासों के बाद कृषि मंत्री नेताम ने आश्वस्त किया कि किसानों की बीमा राशि की समस्या का समाधान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हितग्राहियों के खातों में जल्द ही राशि भेज दी जाएगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।

किसानों ने जताया भरोसा और आभार- मंत्री से सकारात्मक जवाब मिलने पर किसानों ने राहत की सांस ली और श्री भाटिया का आभार जताया। किसानों ने कहा कि आपने पिछली बार भी हमारी बीमा राशि समय पर दिलाई थी, इस बार भी हमें आप पर पूरा भरोसा है।

उपस्थित रहे ये किसान : इस दौरान प्रमुख रूप से ग्राम खोभा से लिलार सिंह मंडावी, देवदास साहू, राजेश्वर, कौशल, ईश्वरलाल साहू, प्रेम लाल साहू, बलवंत दास, गोपाल साहू, शत्रुघ्न, खोमन लाल, चैन दास, ग्राम शिकारी महका से नोहर सिंह, नारायण, खेदूराम, पुराणिक कोर्राम, दुकालूराम और ग्राम मगरधोखरा से प्रेम, नंदेश्वर, छन्नूराम, संतोष कुमार, शांतनु समेत अन्य किसान उपस्थित रहे। किसानों को अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनकी मेहनत का हक उन्हें मिलेगा और संकट से राहत मिलेगी।

छह साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

जशपुर। जिले के चौकी पंडरा पाठ में अपहरण, मारपीट व एससी/एसटी मामले में पिछले 6 सालों से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 29.09.18 को चौकी पंडरापाठ क्षेत्रांतर्गत विशेष संरक्षित समाज के प्रार्थी संत कुमार, उम्र 23 वर्ष ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि उसका एक लड़की से प्रेम सम्बन्ध था, दोनो आपसी सहमति से 05.08.18 को भाग कर, एक रिश्तेदार के यहां, गौरेला पेंड्रा मारवाही में रहे, फिर वहां से रांची झारखंड जाकर काम किए, फिर वहां से वापस 28.08.18 को चौकी पंडरा पाठ क्षेत्रांतर्गत एक गांव में आकर रहने लगे, इसी दौरान दिनांक 29.09.2018 की शाम करीबन 05 बजे, लड़की का मामा शिव कुमार यादव, अपने अन्य साथियों के साथ आकर प्रार्थी को अपने समाज की लड़की

बलरामपुर से सुकमा और कबीरधाम से महासमुंद तक सड़कों पर उतरा शिक्षकों का जन सैलाब

राजनांदगांव (समय दर्शन)। प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक आज एक बार फिर से स्कूलों की पढ़ाई छोड़ सड़कों पर उतरे। शिक्षकों ने राज्य सरकार को साफ-साफऔर दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में राज्यभर के सभी स्कूलों में तालेबंदी कर वे सभी अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे और सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रदेश संचालक संजय शर्मा, मनीष मिश्रा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत एवं जाकेश साहू ने विभिन्न जिलों में आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के पहले प्रदेश के समस्त शिक्षकों से कई वादा किए थे जिसे मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था। जिसमें सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने, क्रमोन्नत वेतनमान देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, प्रथम सेवा गणना करने, पदोन्नति करने सहित अनेकों लिखित एवं मौखिक वादे किए गए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार ने एक भी वादे पूरी नहीं की है।

प्रदेश संचालक कृष्णकुमार नवरंग, राजनारायण द्विवेदी, भूपेंद्र बनाफरए शंकर लाल साहू, भूपेंद्र गिलहरे, चेतन बघेल, गिरीश केशकर एवं लैलूंन भरतद्वाज आदि ने विभिन्न ब्लॉकों में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों से विवाद मोल ले रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटाई जा रही है। प्रदेश के आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बाते कही जा रही है, लेकिन जब शिक्षकों को ही स्कूलों से हटाएंगे और स्कूलों को बंद करेंगे तो कहां से शिक्षा में गुणवत्ता आएगी।

प्रदेश संचालक प्रदीप पांडे, प्रदीप लहरे, राजकिशोर तिवारी, कमल दास मुरचले, प्रीतम कोशले, विक्रम राय, विष्णु प्रसाद साहू, धरम दास बंजारे एवं अनिल कुमार टोप्पो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षिका सोना साहू को माननीय न्यायालय के आदेश पर एरियर्स राशि सहित क्रमोन्नति वेतनमान दिया गया है। लेकिन उक्त आदेश का पालन राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से अभी तक नहीं किया गया है। प्रदेश के शिक्षकों ने मांग की है कि सोना साहू के तर्ज पर राज्य के सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का एरियर्स राशि सहित लाभ दिया जाए। साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पेंशन सहित समस्त लाभ दी जाए। पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर डीएड योग्यताधारीयों को भी पदोन्नत किया जाए तथा 2008 के सेटअप को लागू करके युक्तिकरण किया जाए एवं वर्तमान में हुए युक्तिकरण को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।

शिक्षक साझा मंच के समस्त 23 प्रदेश संचालकों ने विभिन्न जिलों एवं ब्लॉकों में राज्य सरकार को सीधे-सीधे और दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि आज प्रदेश के पूरे सभी 146 विकासखंडों में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर स्कूलों को छोड़कर सड़कों पर उतरे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, यदि आने वाले दिनों में सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो प्रदेशभर के स्कूलों में तालेबंदी कर सभी शिक्षक सड़क पर उतरकर अपने मांगों के लिए संघर्ष करेंगे एवं बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित होने पर जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश में किसानों को समय पर नहीं मिल रहा खाद-बीज : चातुरी नंद

विधायक चातुरी नंद के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किया पुटका सोसायटी का घेराव

सरायपाली(समय दर्शन)। सरायपाली के क्षेत्रीय विधायक चातुरी नंद के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पुटका सहकारी समिति का घेराव किया। वे किसानों के लिए खाद-बीज की मांग कर रहे हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका के नाम सोसायटी प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। मीडिया को जारी किए प्रेस विज्ञप्ति में विधायक चातुरी नंद ने कहा कि क्षेत्र के सोसायटियों में लगातार खाद की किल्लत बनी हुई है। उच्चाधिकारियों को किसानों की समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा रही है जिससे किसान खेती में पिछड़ रहे है। विधायक नंद ने यह भी कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से किसान परेशान है। मानसून सत्र पहुंचने के बाद भी सरायपाली क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में खाद की कमी से लगातार बनी हुई हैं। सेवा सहकारी समितियो में आज तक खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण नहीं किया गया है, जिससे किसानों को खाद्य आपूर्ति करने में राज्य सरकार विफल हो गई है। किसानों को खाद्य भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराने का सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश के किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे है।

इस अवसर पर कांग्रेस नेत्री एवं कार्यक्रम प्रभारी मंदाकिनी साहू, ब्लाक कांग्रेस कमेटी छुहीपाली अध्यक्ष बलराम भोई, जनपद सदस्य पूजा तिवारी, तीरीथ बाई मानिकपुरी, निलेश तिवारी, विक्की तिवारी, माखन मिश्रा, नवीन यादव, धनीराम बरिहा, पांडव, निराकार, टीकाराम, परमेश्वर, प्रहलाद सहित कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

धूमधाम से मनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन, किया वृक्षारोपण

राजनांदगांव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन जिले में उत्साह और पर्यावरणीय संकल्प के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष इमानवेल सिंह के नेतृत्व में डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कलडबरी स्थित एप्पल वेली पब्लिक स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया गया।

इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने विभिन्न छायादार और फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष इमानवेल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सदैव जनहित, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के पक्षधर रहे हैं। उनके जन्मदिन को सेवा और प्रकृति के प्रति संकल्प के रूप में मनाना समाजवादी विचारधारा की पहचान है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी न सिर्फ राजनीति में बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाती रही है। पौधारोपण एक छोटा प्रयास है, लेकिन यही प्रयास आने वाले समय में हरियाली और जीवनदायिनी वातावरण को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा।

कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश साहू, प्रदेश अध्यक्ष किसान एकता संगठन बृजेश चौरसिया, प्रदेश सचिव मोतीलाल यादव, विष्णु कुमार सोनी, मन्नू लाल सोनी, जिला सचिव रवि ठाकुर, महिला जिला अध्यक्ष मिनाक्षी वर्मा, एप्पल वेली पब्लिक स्कूल के रिचर्डसन जॉन, प्राचार्या आराधना सिंह, शिक्षक कंचन, पूजा वर्मा सहित कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी ने अखिलेश यादव के दीर्घायु और सक्रिय राजनीतिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम के अंत में वृक्षों की देख-रेख और संरक्षण का भी संकल्प लिया गया।

7 जुलाई को होने वाले किसान जवान संविधान जनसभा को सफल बनाने मध्य ब्लॉक कांग्रेस दुर्ग ने बनाया वार्ड प्रभारी

दुर्ग (समय दर्शन)। आगामी 7 जुलाई को रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे विशेष रूप से उपस्थिति रहकरकिसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करने वाले हैं इस जनसभा को सफल बनाने के लिए मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अलताफ अहमद ने पूर्व विधायक अरुण वोरा की अनुशंसा पर एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष गया पटेल का अनुमोदन पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अंतर्गत आने वाले 12 वार्डों में 12 वार्ड प्रभारी नियुक्त किए हैं जो वार्डों में बैठक लेकर होने वाली जनसभा मैं कांग्रेस जनों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करेंगे।

वार्ड प्रभारी सर्वप्रथम राजकुमार वर्मा (पूर्व पार्षद) वार्ड नंबर 30 तमेरपारा वार्ड, गणेश सोनी वार्ड नंबर 31 आपापुरा वार्ड, हितेश सेन वार्ड नंबर 32 ब्राह्मण पारा वार्ड, चंद्रशेखर पारख वार्ड नंबर 33 चंडी मंदिर वार्ड, डोमारसिंह राजपूत वार्ड नंबर 34 शिवपारा वार्ड, अशोक मेहरा (पूर्व पार्षद) वार्ड नंबर 35 रामदेव मंदिर वार्ड, अलख नवरंग वार्ड नंबर 36 गंजपारा वार्ड,सुश्री सरिता ताम्रकार वार्ड नंबर 37 आजाद वार्ड,यश बाकलीवाल वार्ड नंबर 38 मीलपारा वार्ड, सुश्री मीना मानिकपुरी वार्ड नंबर 39 कचहरी वार्ड, समयलाल साहू वार्ड नंबर 40 सुराना कॉलेज वार्ड, हेमंत तिवारी वार्ड नंबर 55 पुलगाँव वार्ड प्रभारी बनाए गए हैं जो शीघ्र ही बैठक लेंगे।

शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध प्राइवेट स्कूल, क्रिष्टोफर पॉल ने की बंद करने की मांग

राजनांदगांव। शिक्षा के अधिकार कानून और राज्य शासन के निर्देशों के बावजूद शहर में कई अवैध व सुविधाविहीन प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने इन स्कूलों को तुरंत बंद करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना मान्यता और बुनियादी सुविधाओं के ये स्कूल मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्री पॉल ने बताया कि लिटिल मिलेनियम प्ले स्कूल (गुरुनानक चौक), अजीज पब्लिक स्कूल (जीई रोड), संस्कार किड्स (स्टेडियम के पास) जैसे दर्जनों स्कूल लंबे समय से संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों में न तो खेलने का मैदान है और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इन शर्तों की पूर्ति अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद ये स्कूल बेरोकटोक चल रहे हैं। उन्होंने चैतन्य टेक्नो स्कूल का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम चला रहा है जबकि न राज्य सरकार से एनओसी मिली है और न ही सीबीएसई या जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से मान्यता। ऐसी स्थिति में इसे केवल सीजी बोर्ड का पाठ्यक्रम ही संचालित करना चाहिए, लेकिन बार-बार लिखित शिकायत के बावजूद अब तक कोई जांच नहीं की गई है। श्री पॉल ने कहा कि राज्य में शिक्षा संहिता, फीस नियंत्रण अधिनियम और मान्यता नियमों के तहत स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी और मिलीभगत के चलते लगभग 20 से ज्यादा अवैध और सुविधाविहीन प्राइवेट स्कूल बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अवैध स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और शिक्षा के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे जनहित में आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

शिक्षकों का राज्यव्यापी हल्ला बोल आंदोलन: 1 जुलाई को 146 विकासखंड मुख्यालयों पर होगा धरना प्रदर्शन

चार सूत्रीय मांगों पर केंद्र और न्यायपालिका से हस्तक्षेप की अपील, पोस्ट कार्ड अभियान की हुई शुरुआत

मुंगेली/ समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षकों का आक्रोश अब उबाल पर है। शिक्षक साझा मंच के बैनर तले प्रदेशभर के शिक्षक एकजुट होकर 1 जुलाई को राज्य के सभी 146 विकासखंड मुख्यालयों पर एक साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन राज्य सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों और युक्तियुक्तकरण में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध है।

चार सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान शुरू- शिक्षक साझा मंच ने चार मुख्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग की है। इसके लिए पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत मुंगेली जिले से की गई है, जो आगे चलकर पूरे प्रदेश में विस्तारित होगा।

चार सूत्रीय मांगें इस प्रकार हैं:

सेटअप 08 की पुनर्बहाली (स्ह्लड्डह्लह्वह्य त्तह्वश्र) को यथावत रखा जाए।

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार और मनमानी की उच्च स्तरीय जांच हो।

गंभीर बीमार, महिला शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों का दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरण रद्द किया जाए।कटौती की गई 9,000 से अधिक पदों को पुनः बहाल कर 57,000 पदों पर भर्ती की जाए।सरकार पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप प्रदेश संचालक कृष्णकुमार नवरंग ने राज्य सरकार पर शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। गंभीर बीमार, महिला शिक्षकों और सेवा निवृत्त शिक्षकों को 300 से 400 किलोमीटर दूर भेजा गया, जबकि भाई-भतीजावाद और सिफारिशों के बल पर नियमों को ताक पर रखकर स्थानांतरण किए गए।काली पट्टी बांधकर स्कूलों में कार्य और अब सीधा जन आंदोलन आंदोलन के पहले चरण में राजधानी में प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। अब आंदोलन के दूसरे चरण में वे सीधे प्रधानमंत्री की 'गारंटी' पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार इस गारंटी को पूरा करने में विफल रही है।आंदोलन का नेतृत्व और विस्तार से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे शिक्षक साझा मंच के प्रदेश संचालक कृष्णकुमार नवरंग ने कहा कि यह आंदोलन केवल शिक्षकों के हित का नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता बचाने की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती, यह जन आंदोलन जारी रहेगा।

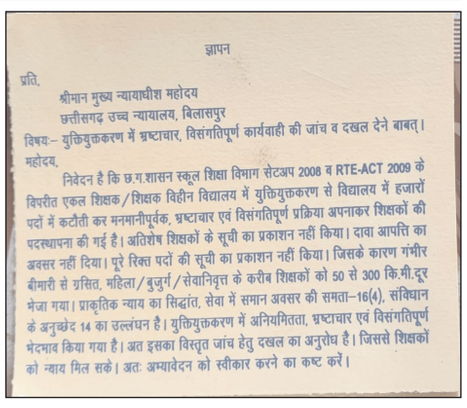

ज्ञापन

प्रति,
श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विषयः- युक्तियुक्तकरण में भ्रष्टाचार, विसंगतिपूर्ण कार्यवाही की जांच व दखल देने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप 2008 व RTE-ACT 2009 के विपरीत एकल शिक्षक/शिक्षक विहीन विद्यालय में युक्तियुक्तकरण से विद्यालय में हजारों पदों में कटौती कर मनमानीपूर्वक, भ्रष्टाचार एवं विसंगतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। अतिशेष शिक्षकों के सूची का प्रकाशन नहीं किया। दावा आपत्ति का अवसर नहीं दिया। पूरे रिक्त पदों की सूची का प्रकाशन नहीं किया। जिसके कारण गंभीर बीमारी से ग्रसित, महिला/बुजुर्ग/सेवानिवृत्त के करीब शिक्षकों को 50 से 300 कि.मी.दूर भेजा गया। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, सेवा में समान अवसर की समता-16(4), संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। युक्तियुक्तकरण में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विसंगतिपूर्ण भेदभाव किया गया है। अत इसका विस्तृत जांच हेतु दखल का अनुरोध है। जिससे शिक्षकों को न्याय मिल सके। अतः अभ्यावेदन को स्वीकार करने का कष्ट करें।

यह आंदोलन प्रदेश के शिक्षक संगठनों की एकजुटता और शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए किए जा रहे संघर्ष का प्रतीक बनता जा रहा है। आगामी 1 जुलाई को राज्य भर के विकासखंड मुख्यालयों पर शिक्षक शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिल सकता है।

संक्षिप्त समाचार

लखमा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने चौथा पूरक चालान पेश किया

रायपुर (समय दर्शन)। शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ सोमवार को ईओडब्ल्यू ने चौथा पूरक चालान पेश किया। विशेष कोर्ट में 1100 पन्नों का चालान पेश किया गया। इस चार्जशीट में पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को शराब घोटाले से बतौर कमिशन मिला 64 करोड़ रुपये मिलने की बात कही गई है।

चार्जशीट में एसीबी ने बताया है कि कवासी लखमा वर्ष 2019 से 2023 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री रहे। जांच में साक्ष्यों और वित्तीय विश्लेषण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ है कि कवासी लखमा, जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन थे, उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की, बल्कि मंत्री पद की शक्तियों का उपयोग कर नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप, अधिकारियों की पदस्थापना में प्रभाव, टेंडर प्रक्रियाओं में विकृति और नगद लेन-देन की एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कर पूरे विभागीय तंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से संचालित किया गया।

लखमा के संरक्षण में अधकारियों ने दिया घोटाले को अंजाम- ACB ने अपने चार्जशीट में कहा है कि, मंत्री के संरक्षण में विभागीय अधिकारियों, सहयोगियों और ठेकेदारों के माध्यम से सुनियोजित घोटाले को अंजाम दिया गया। कमिशन के रूप में अर्जित राशि को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए उपयोग कर भारी मात्रा में असम्यक लाभ अर्जित किया गया। एसीबी ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि अब तक की विवेचना में कवासी लखमा को 64 करोड रुपये आबकारी घोटाले के फ्लस्वरूप उनके हिस्से में प्राप्त होना प्रमाणित हुआ है। जिसमें 18 करोड़ रुपये के अवैध धन राशि के निवेश- खर्च संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

मुख्य सचिव पद पर अमिताभ जैन को मिला एक्सटेंशन, कैबिनेट बैठक में मुहर

रायपुर (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सेवा विस्तार मिल गया है। सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी इस पर अपनी औपचारिक सहमति दे दी है। इस निर्णय के साथ ही अमिताभ जैन फ़िलहाल मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई देने की तैयारी थी और प्रशासनिक गलियारों में नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चाएं तेज थीं। इस पद की दौड़ में तीन वरिष्ठ ड्ब्लू अधिकारियों के नाम सबसे आगे माने जा रहे थे—1992 बैच के सुब्रत साहू, 1993 बैच के केंद्र प्रतिनियुक्त अमित अग्रवाल, और 1994 बैच के मनोज पिंगुआ। हालांकि, दोपहर बाद हुए निर्णय ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया और अमिताभ जैन को सेवा विस्तार देकर यथावत बनाए रखने का फैसला किया गया। यह कदम प्रशासनिक स्थिरता और अनुभव के मद्देनज़र उठाया गया माना जा रहा है। अमिताभ जैन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनकी कार्यशैली तथा अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।

छत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन में अधिकारियों की अहम भूमिका: वित्त मंत्री

रायपुर (समय दर्शन)। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के नीति प्रबंधन और नियंत्रण में राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों की सराहना की और कहा कि राज्य के वित्तीय प्रबंधन में वित्त अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने वित्त सेवा के अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और सजगता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वित्त मंत्री चौधरी आज राजधानी रायपुर के न्यू-सर्किट हाऊस में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक आमसभा एवं स्नेह सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ की विभिन्न मांगों पर आवश्यक पहल करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने संघ की वेबसाईट का शुभारंभ तथा स्मारिका 'सुनिधि' का विमोचन तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों को शॉल, श्रीफ्ल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन आर.एस. विश्वकर्मा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव वित्त विभाग, चंदन कुमार, विशेष सचिव वित्त विभाग एवं रितेश अग्रवाल, संचालक कोष एवं लेखा शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने बौद्धिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले के युवाओं से की मुलाकात

खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ है: मुख्यमंत्री साय

रायपुर (समय दर्शन)। मुख्यमंत्री साय ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में बौद्धिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले के युवाओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने युवाओं से उनका हाल-चाल जाना और राजधानी में उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री से मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के युवाओं से आत्मीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सली विकास विरोधी हैं। वे नहीं चाहते कि बस्तर के लोगों को पानी, बिजली, सड़क और विद्यालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलें। सरकार की प्राथमिकता बस्तर का विकास है। बहुत जल्द बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा। मुख्यमंत्री ने बड़े प्रेम से प्रदेश के सुदूर क्षेत्र से आये इन युवाओं से बातचीत की और उनके बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने युवाओं से पूछा कि उन्हें रायपुर आकर कैसा लग रहा है ? जिसके जवाब में युवाओं ने बताया कि उनके दल के अधिकतर युवा पहली बार राजधानी रायपुर आये हैं। अधिकांश ने इस भ्रमण के दौरान पहली बार जगदलपुर को देखा। पहली बार अपने गांव से रायपुर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नई-नई चीजें देखने को मिल रही हैं। आज उन्हें मंत्रालय को देखने और यहां की कार्यप्रणाली समझने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से यह अनुभव आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस भ्रमण का पूरा लाभ उठाएं और स्वयं को समृद्ध करें। मुख्यमंत्री साय ने सुकमा के युवाओं से विशेष रुप से उनकी शिक्षा के विषय में चर्चा की। विभिन्न आयुवर्ग के युवाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे दसवीं, बारहवीं सहित कॉलेज तक में पढ़ रहे हैं। सहज सरल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से युवाओं ने खुलकर संवाद किया। इस दौरान एक छात्र ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह बीएससी के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, वहीं एक छात्र ने स्वयं खड़े होकर मुख्यमंत्री को बताया कि वह भी बीए फाइनल का विद्यार्थी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की पढ़ाई के प्रति रुचि की सराहना की और इसी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत नियद नेल्लानार कार्यक्रम के तहत बस्तर संभाग के युवाओं का बौद्धिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में सुकमा जिले के 95 युवाओं को 2 दिवसीय भ्रमण पर राजधानी रायपुर आये हैं।

इटावा की घटना के खिलाफ यादव समाज लामबंद

रायपुर (समय दर्शन)। विगत दिनों इटावा के बकेवर इलाके के दानदरपुर गांव में कथा वाचक एवं उनके सहायकों को उच्च जाति के लोगों द्वारा की गई मारपीट करने वालों पर कड़ी करवाई करने की मांग बाबत ज्ञापन लेकर आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील यादव महासंघ एवं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के संयुक्त तत्वाधान में में श्री निरंजन सिंह यादव, इंजीनियर एस डी यादव, श्री जितेंद्र बहादुर, यादव, श्री भुवनेशवर यादव, सुश्री शोभा यादव, श्री कमल सिंह यादव, श्री संजय यादव, श्री रविंद्र सिंह यादव, श्री उपेंद्र यादव, श्री लीलाधर यादव, श्री अनिल यादव, श्री निरंजन नीरू, श्री अशोक यादव, श्री राहुल यादव, शशिकांत यादव, राजेश यादव एवं समाज के अन्य गणमान्य कृष्णसखाओं ने रायपुर जिला कलेक्टर श्री गौरव कुमार सिंह से सौजन्य भेंट के दौरान अपनी आहत भावनाओं से अवगत कराया।। जिलाधीश महोदय को सौंपे मेमोरेंडम में यदुवंशी संगठन ने मांग रखी कि हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, उसके बाद भी कथा के दरम्यान कुछ उच्च वर्ग के दबंगों द्वारा कथा व्यास से उनकी जाति पूछी गई। कथा वाचक के अपनी जाति यादव बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादियों लोगों ने कथा व्यास से अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई, पैर पढ़वाने के साथ मारपीट भी की तथा स्थल का शुद्धिकरण भी करवाया ।। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के यादव संगठन के महासचिव द्वय निरंजन सिंह यादव और एस डी यादव ने ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि सभी संदिग्ध और संलिप्त आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो एवं यथोचित धारा में प्रकरण दर्ज किया जाए, अन्यथा बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया जाएगा ।।

खदानों में दक्ष संचालन के लिए अदाणी समूह का नया प्रशिक्षण अभियान शुरू

आईडीटीआर के सहयोग से मिलेगा भारी मशीनों व तकनीकी वाहनों को चलाने उत्कृष्ट प्रशिक्षण

रायपुर: अदाणी समूह की कौशल विकास की प्रमुख संस्था अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन ने खदानों में भारी मशीनों और वाहनों को चलाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ड्राइविंग और यातायात अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), छत्तीसगढ़ के सहयोग से नवा रायपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को 25 युवाओं के एक नए प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ किया गया। अदाणी समूह की सामाजिक सरोकार की पहल के तहत छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्य के लगभग 103 युवाओं के कौशल विकास संवर्धन हेतु भारी और तकनीकी वाहनों को चलाना सिखाया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अदाणी समूह के परियोजना प्रभावित गाँवों में युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस बैच में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार तहसील में स्थित जीपी 2 व 3 खदानों से 30 लोग, सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील के पीईकेबी और पीसीबी खदानों से 13 युवाओं सहित मध्यप्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के सुलयारी तहसील से 50 तथा उड़ीसा राज्य के तालाबीरा से 10 प्रतिभागी शामिल हैं, जिन्हें हैवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) के 40 दिनों में 240 घंटों और हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) के 35 दिनों में 200 घंटों के निःशुल्क प्रशिक्षण में कुशल किया जाएगा। इन सभी को यहाँ प्रशिक्षण सहित होस्टल में रहने खाने सहित संपूर्ण व्यवस्था का खर्च अदाणी समूह द्वारा वहन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा 20 प्रतिशत कोयला उत्पादित करता है। ऐसे में, भारी वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित चालाकों के लिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं, किन्तु उन्हें प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की आज भी कमी है। ऐसे में, अदाणी समूह की यह पहल ग्रामीण युवा, परिवहन और खनन उद्योग के लिए लाभदायी होगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए रेखांकित किया गया है। शुभारंभ समारोह में अहमदाबाद से अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफ्सिर- कोल माइनिंग श्री मनोज कुमार शाही ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति दी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्लस्टर के मानव संसाधन प्रमुख श्री राम द्विवेदी, तालाबीरा क्लस्टर के चीफ श्री नवल शर्मा, अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन के श्री रवि रेमी, तमनार क्लस्टर के सीएसआर प्रमुख श्री मनीष शुक्ला, आईडीटीआर के संयुक्त निदेशक श्री अमित गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

राजधानी में ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस की सख्तीः 10 वाहन चालक पकड़ाए

सभी के लाइसेंस निलंबित होंगे

रायपुर (समय दर्शन)। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी है। शनिवार और रविवार की रात शहर के प्रमुख चौराहों पर चलाए गए चेकिंग अभियान में ड्रंक एंड ड्राइव के तहत 10 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। सभी मामलों में चालान काटकर प्रकरण न्यायालय भेजा गया है, साथ ही संबंधित चालकों के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) डॉ. प्रशांत शुक्ला के

मार्गदर्शन में श्रीराम मंदिर चौक, फुंडहर चौक और तेलीबांधा थाना चौक पर रात 11 बजे से 2 बजे तक बेरिकेटिंग कर विशेष जांच अभियान चलाया गया।

अब तक 860 पर कार्रवाई, भारी जुर्माना- रायपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में अब तक 860 ड्रंक एंड ड्राइव वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन मामलों में वाहनों को जब्त कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां ?10,000 से ?15,000 तक का जुर्माना लगाया गया। साथ ही चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही भी की जा रही है।

पुलिस की अपील

यातायात पुलिस रायपुर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं, क्योंकि यह न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक है। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफसख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

रेल मंडल में स्पोर्ट्स कोटे के पदों पर जल्द भर्ती के दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ में चल रहा 46 हजार करोड़ का रेलवे का कामः बृजमोहन

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को रायपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल यात्री सुविधाओं, नई रेल परियोजनाओं, औद्योगिक विकास, और पर्यावरणीय उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए एक रणनीतिक राज्य है, जहां से देश की रेलवे को कुल आमदनी का 16त्न प्राप्त होता है। राज्य में 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन धीमी गति से काम होने के कारण आम जनता में असंतोष है। उन्होंने रेल अधिकारियों को इन कार्यों में गति लाने और तय समयसीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बन रहे अंडरपास और ओवरब्रिज कार्यों की समीक्षा कर, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पूर्ण किया जाए। साथ ही, नई रेल लाइनों के निर्माण से पूर्व स्थानीय सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर सुझाव लेने की आवश्यकता बताई। उन्होंने दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस में कोच वृद्धि और इसके नागपुर तक विस्तार, रीवा-बिलासपुर ट्रेन को रायपुर-दुर्ग तक विस्तारित करने और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने रेलवे ट्रैक के आसपास पौधारोपण की कार्ययोजना 7 दिन में प्रस्तुत करने और स्टेशनों पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल लगाने की बात कही। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में स्टॉल की संख्या बढ़ाने और देवभोग और छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने हेतु महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा गढ़ कलेवा की तर्ज पर स्टॉल स्थापित करने के निर्देश दिए। जिससे युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बैठक में रावघाट-धमतरी कनेक्टिविटी, औद्योगिक कॉरिडोर की प्रगति, रायपुर-अभनपुर रेल लाइन के धमतरी तक विस्तार, परमालकसा-खरसिया प्रस्तावित रेल लाइन के तहत आने वाले गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने के निर्देश दिए इस प्रतिबंधों के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है वहीं रावघाट में रेल लाइन के प्रभावित ग्रामीणों को नौकरी देने जैसे प्रमुख मुद्दे भी उठाए गए। बैठक में ट्रेनों के ठहराव, नई ट्रेनों के संचालन, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोलने, कुली, वेंडर और हम्मालों को सुविधाएं देने जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सांसद अग्रवाल ने ट्रेनों के निरस्तीकरण और लेटलतीफी पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने, स्टेशनों के उन्नयन (अमृत स्टेशन योजना), आरक्षण कोटा बढ़ाने, उन्होंने केंद्र को पत्र लिखकर रायपुर से पुरी तक वंदे भारत ट्रेन और छत्तीसगढ़ से रत्नागिरी व गोवा तक सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग करने की बात कही। बिलासपुर से नाथद्वारा (राजस्थान) सीधी ट्रेन चलाने, रायपुर से जोधपुर (भगत की कोठी) को सप्ताह में पांच दिन चलाने, मध्य रेल मंडल नागपुर एवं रेल जोन कार्यालय मुंबई से संचालित ट्रेन 12105-12106 विदर्भ एक्सप्रेस (मुंबई गोदिया), 12114- 12135 (नागपुर- पुणे, पुणु नागपुर एक्सप्रेस) 11040-11039 पूणे- भंडारा, भंडारा - पुणे महाराष्ट्र एक्सप्रेस को रायपुर / बिलासपुर तक विस्तारित करने, बिलासपुर से चलने वाली ट्रेनों बिलासपुर-चेन्नई (12851-52), साप्ताहिक एक्सप्रेस बिलासपुर-हापा (22939-40). बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (20825-826) एवं बिलासपुर नई दिल्ली (12441-42) का भाटापारा में स्टापेज दिए जाने, पूरी-दुर्ग (18425-18426) और संबलपुर-नांदेड (18309-18310) के संतला (एसएफसी) रेलवे स्टेशन पर विस्तार, दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस, 18201 को सप्ताह में पांच दिन चलाने, गोंदिया जबलपुर पैसेंजर ट्रेन को रायपुर तक चलाने, कोरोना काल के समय से बंद ट्रेन स्टॉपेज पुनः बहाल करने।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक -3, शंकर नगर पानी, टंकी के नीचे
Email:- rmczonex@gmail.com

क्रमांक 12/ न.पा.नि./जोन-3/2025-26 रायपुर, दिनांक 01.07.2025

द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

नगर पालिक निगम, रायपुर जोन क्र. 03 अंतर्गत रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के माध्यम से जोन क्रमांक-03 अंतर्गत जोन कार्यालय परिसर, सभी शासकीय, आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों में वर्षा जल संरक्षण एवं भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के कार्य हेतु राशि रु. 5.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इच्छुक पंजीकृत अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.). स्व-सहायता समूह, असंगठित कामगारों की पंजीकृत समितियां, बेरोजगार इंजीनियर्स एवं निगम से पंजीकृत हाईड्रोलॉजिस्ट एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से बंद लिफाफे में दरे दिनांक 08.07.2025 तक आवेदनकर्ता फर्म/संस्था का जीवित पंजीयन, पैन कार्ड, जी.एस.टी. संलग्न कर अमानती राशि का एफडी.आर. राशि रू. 5000/- (जोन आयुक्त जोन क्र. 03 नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से) का स्पीड पोस्ट के माध्यम से सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

उक्त कार्य हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का डी.डी. राशि रू. 2000/- जोन आयुक्त जोन क्र. 03 नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से दिनांक 04.07.2025 सायं 5.00 बजे तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। दरे सभी करो को सम्मिलित कर होगी तथा कटौतियां भी शासन के नियमों के अंतर्गत की जावेगी। (स्व-सहायता समूह / असंगठित कर्मचारी पंजीकृत समितियों को धरोहर राशि में छूट की पात्रता होगी)

इस कार्य हेतु अन्य जानकारियों, नियम व शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यपालन अभियंता जोन क्र. 03 नगर पालिक निगम, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है।

जोन ओयुक्त
जोन क्रमांक -3
नगर पालिक निगम, रायपुर

संपादकीय

नकदी की बरामदगी साफ कदाचार की घटना

भारत में जैसे भ्रष्टाचार को लगभग स्वीकृति सी मिल चुकी है, किसी भी विभाग में कोई भी काम कराना हो चपरासी से लेकर अफसर तक सबकी यथायोग्य भेंट पूजा को आम जनता ने खुशी से आत्मसात सा कर लिया है। आए दिन पड़ने वाले छापों में होने वाली ऊपर की कमाई की बरामदगी की खबरा से कोई नहीं चौंकता, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में 14 मार्च की आधी रात को लगी आग बुझाने पहुंचे अग्निशमन कर्मियों को अधजले नोटों की गड्डियां मिलने की खबर जब आई थी तो सब चौंक गए थे। जज के घर से नकदी की बरामदगी साफ कदाचार की घटना थी, मगर कार्रवाई के नाम पर उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। वर्मा खुद को निदरेष बताते हुए अपने खिलाफ षडयंत्र की बात कहते रहे। मामले की जांच के लिए गठित समिति की शुरुआती रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुमरू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर चुके हैं। अब जो ब्योरा सामने आया है; उसके तहत जांच समिति ने 10 दिन की पड़ताल और 55 गवाहों के बयान के आधार जज वर्मा के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए हैं और उन्हें हटाने की सिफारिश की है। अब जो ब्योरा सामने आया है; उसके तहत जांच समिति ने 10 दिन की पड़ताल और 55 गवाहों के बयान के आधार जज वर्मा के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए हैं और उन्हें हटाने की सिफारिश की है। 64 पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने जस्टिस वर्मा की बेगुनाही की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अग्निकांड के अगले ही दिन तड़के कोठी से अधजले नोटों की सफाई कर देने की घटना ने बड़ा मात्रा में नकदी होने के संदेहों को पुख्ता कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस वर्मा के घरेलू स्टाफ ने अपने मालिक के पक्ष में बयान दिए, लेकिन अग्निशमन और दिल्ली पुलिस के स्वतंत्र गवाहों के बयान से साफ है कि जज के सरकारी आवास पर 4-5 बोरियों में नोटों की गड्डियां थीं। परस्पर विरोधी बयानों का विश्लेषण करने के बाद समिति ने घरेलू कर्मचारियों का झूठ पकड़ लिया। समिति ने पाया कि जस्टिस वर्मा की दलीलें सच्चाई से कोसों दूर हैं। पाया गया कि स्टोर पर घर वालों का गुप्त या सक्रिय नियंत्रण था। घटना की एफआईआर न कराने और वर्मा के चुप्पी साध लेने से मामला खुल गया।

वन पट्टों के फौती और नामांतरण की प्रक्रिया अब आसान

जी.एस. केशरवानी

छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल से वन पट्टों के फौती नामांतरण की प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित हो गई है। किसी पट्टाधारी की मृत्यु के बाद उसके वैध वारिसों को अधिकार अब आसानी से मिल रहा है। वारिसों के नाम पर पट्टा दर्ज होने से वे न केवल भूमि के वैधानिक स्वामी बन पा रहे हैं, बल्कि शासकीय योजनाओं का लाभ भी उन्हें सुलभता से मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रत्येक वनभूमि पट्टाधारी परिवार को उसका पूरा हक और सम्मान दिलाना, हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। देश में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 23 लाख 88 हजार 834 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रो का वितरण मार्च 2025 तक किया गया है, इनमें छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 4 लाख 82 हजार 471 व्यक्तिगत वन पत्रधारक हैं। राज्य में वन पट्टाधारकों की यह संख्या देश में सर्वाधिक है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन वर्ष 2008 से देश में हो रहा है लेकिन इस अधिनियम में वन अधिकार पत्रधारक की मृत्यु होने की दशा में उनके विधिक वारिसानों को भूमि के नामांतरण के संबंध में प्रक्रिया नहीं होने के कारण नामांतरण नहीं हो पा रहा था साथ ही उन्हें शासन के योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर इस कठिनाई को दूर करने के लिए तथा वंशजों का नाम पर काबिज वनभूमि का हस्तांतरण एवं राजस्व तथा वन अभिलेखों में दर्ज करने का निर्णय लिया। वन पट्टों के फौति-नामांतरण की सरल प्रक्रिया तय की गई है। अकेले छत्तीसगढ़ में ही 11 हजार 600 से अधिक वंशजों के आवेदन इसके लिए प्राप्त हुए हैं, जिन्हें प्रक्रिया के अभाव में नामांतरण के लिए भटकना पड़ रहा है। राज्य सरकार के इस निर्णय से अब उन्हें उनकी समस्या का निदान मिल गया है। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मोर जंगल, मोर जमीन, मोर वन अधिकार के माध्यम से वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासियों द्वारा काबिज पैतृक भूमि पर वन अधिकारों की मान्यता प्रदान की जा रही है। साथ ही पत्रधारकों के अभिलेख दुरुस्तीकरण एवं डिजिटलाईजेशन, नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन संबंधी कार्य सुगमता से हो रहा है। राज्य में नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, त्रुटि सुधार एवं अपील के अंतर्गत अब तक प्राप्त 11623 आवेदनों में से 3800 आवेदनों का निराकरण किया गया है। इसके फलस्वरुप विधिक वारिसान जो विभिन्न शासकीय योजनाओं तथा अन्य सुविधा से वंचित थे, उन्हे अब पीएम किसान सम्मान निधि, धान खरीदी आदि का लाभ भी मिल रहा है।

नामांतरण प्रक्रिया - नामांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वन अधिकार मान्यता पत्रधारक का निधन होने पर कैफियत कॉलम में दर्ज प्रविष्टि में संशोधन किया जाता है। विधिक वारिसानों के मध्य वन अधिकार पत्र की वन भूमि के बंटवाने की प्रक्रिया-वन अधिकार मान्यता पत्रधारी के जीवनकाल में उनके द्वारा प्रस्तावित या उसकी मृत्यु के उपरांत विधिक वारिसानों के मध्य खाता विभाजन करने की सुविधा दी जा रही है। सरकारी नक्शों में मान्य वन अधिकारों के सीमांकन की कार्रवाई की जाती है। संबंधित विभागों के अभिलेखों में वन अधिकारों को दर्ज करना किया जाता है। वन अधिकार पुस्तिका आदि अभिलेखों में त्रुटि का निराकरण भी किया जा रहा है।

टीएमसी नेताओं की निर्लज्ज टिप्पणियों से उठा विवाद

ललित गर्ग

कोलकाता में कानून की एक छात्रा से सामूहिक दुराचार-गैंगरेप का मुद्दा एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है उतना ही बड़ा नारी उत्पीड़न का मुद्दा बनकर उभर रहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं की अनर्गल एवं निर्लज्ज टिप्पणी स्त्री की मर्यादा, सम्मान एवं अस्मिता के खिलाफ शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण व संवेदनहीन प्रतिक्रिया है। इन नेताओं ने गैंगरेप मामले पर विवादित बयान से राज्य एवं देश में भारी जनाक्रोश पैदा हो गया था। विशेषत: राजनेताओं के बयानों एवं सोच में एक बार फिर शर्मनाक ढंग से पीड़िता पर दोष मढ़ने की बेशर्म कोशिश की गई है। इस मामले में सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी अन्दर एवं बाहर दोनों मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। जहां इस मामले में पार्टी के अन्दर गुटबाजी एक बार फिर सामने आयी है, वहीं भाजपा आक्रामक रूप से ममता सरकार को घेर रही है। टीएमसी की महिला नेत्री महुआ मोइत्रा टीएमसी नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के उन बयानों पर निराशा व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इन राजनेताओं के बयान में स्त्री-द्वेष पार्टी लाइन से परे है।

यह एक बदतर स्थिति है कि जिस पार्टी के नेताओं ने ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए हैं, उस पार्टी की सुप्रीमो एक महिला ही है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि ममता बनर्जी जैसी तेजतर्रार मुख्यमंत्री के शासन और नेतृत्व के वर्षों के दौरान टीएमसी के भीतर नारी सम्मान एवं अस्मिता को लेकर संवेदनशीलता लाने और मानसिकता में बदलाव लाने के प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। अकसर महिलाएं और महिला राजनेता पुरुष नेताओं के हाथों अश्लील, अभद्र और तौहीन भरी टिप्पणओं की शिकार होती रही हैं। ऐसे बयानों के बावजूद अकसर ये राजनेता किसी कठोर कार्रवाई की बजाय हल्की फुल्की फटकार के बाद बच निकलते हैं। ये बयान कभी महिलाओं की बॉडी शेमिंग करते नज़र आते हैं तो कभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को मामूली बताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही ये चिन्ताजनक संदेश भी जाता है कि महिलाओं के बारे में हल्के और आपत्तिजनक बयान देना विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के लिये सामान्य बात है।

जब किसी देश की बेटियां न्याय का अध्ययन कर रही हों और वहीं उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि पूरे समाज, व्यवस्था और सोच के लिए एक जघन्य आइना बन जाती है। प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना ने न केवल राजनीतिक सोच एवं कानून के मंदिरों को शर्मसार किया है, बल्कि हर संवेदनशील मन को झकझोर दिया है। पीड़िता एक लॉ कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा थी, जो अपने उज्ज्वल भविष्य के सपनों के साथ शिक्षा के पथ पर अग्रसर थी। घटना की रात वह अपने कुछ परिचितों के साथ बाहर थी, जिनमें से ही कुछ ने उसकी अस्मिता को रौंद डाला। उसे नशा दिया गया और फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जब कानून पढ़ने वाली लड़की खुद असुरक्षित है, तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? क्या यह कानून की शिक्षा देने वाली संस्थाओं एवं शासन करने वाली सत्ताओं के लिए आत्ममंथन का समय नहीं है? ऐसी घटनाओं पर निर्भया कांड के बाद बने कानूनों का सख्ती से पालन हो। रेप को सिर्फ एक 'जुर्म' नहीं, 'राष्ट्रीय आपदा' माना जाए, और उसकी रोकथाम के लिए शिक्षा, संस्कार और तकनीकी सुरक्षा साधनों को प्राथमिकता दी जाए। कोलकाता की लॉ छात्रा की यह दर्दनाक घटना हमें चेताती है कि केवल कानून बना लेना काफी नहीं, जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक बेटियां असुरक्षित रहेंगी। यह केवल एक छात्रा की लड़ाई नहीं, बल्कि हर बेटी की सुरक्षा की लड़ाई है। न्याय तब होगा जब ऐसी घटनाएं रुकेंगी और उसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा।

सबसे दुखद पहलू यह है कि अनेक बार ऐसी घटनाओं में समाज चुप रहता है, पीड़िता को दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर तंज, मीडिया ट्रायल और व्यक्तिगत चरित्रहनन जैसी बातें पीड़िता को न्याय से अधिक पीड़ा देती हैं। पीड़िता के लिये यह पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब उनके जन-प्रतिनिधि निर्लज्ज बयानबाजी करते हैं। विडंबना यह है कि पीड़िता के प्रति निर्लज्ज बयानबाजी अकेले पश्चिम बंगाल का ही मामला नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी संवेदनहीन टिप्पणियां सामने आती रही हैं। यदि इक्कीसवीं सदी के खुले समाज में हम महिलाओं के प्रति संकीर्णता की दृष्टि से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कि ये वे लोग हैं जिन्हें जनता अपना नेता मानती है और लाखों लोग उन्हें चुनकर जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कानून बनाने व व्यवस्था चलाने भेजते हैं। देश में बढ़ रही यौन-शोषण, रेप एवं नारी दुराचार की घटनाओं को देखते हुए जन-प्रतिनिधियों को ज्यादा संवेदनशील होने की अपेक्षा की जाती है। बड़ा प्रश्न है कि आखिर किसी राजनेता को हर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और यौन शोषण को असंवेदनशील तरीके से देखने की छूट क्यों एवं कैसे मिल जाती है।

भारत ही ऐसा देश है, जहां महिलाओं की अस्मिता एवं अस्तित्व को तार-तार करने वाले नेताओं के निर्लज्ज बयानों के बावजूद उन पर कोई ठोस, सख्त एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती। जबकि विश्व के अन्य देशों में ऐसा नहीं है। जैसे 2017 में ब्रिटेन के एक पार्षद के सामान्य से बयान पर अच्छा खासा बवाल मचा था। पार्षद ने सांसद का चुनाव लड़ रही एक गर्भवती महिला राजनेता के बारे में कह दिया था, 'वो गर्भवती हैं और उनका समय तो नैपी बदलने में ही बीत जाएगा, वो आम लोगों की आवाज़ क्या उठाएंगी?' इसके लिए पार्षद को माफ़ी मांगनी पड़ी। ब्रिटेन जैसे कई देशों में अकसर ऐसे बयानों पर कार्रवाई होती है। मिसाल के तौर पर 2017 में ही यूरोपियन संसद के एक सांसद ने बयान दिया था कि महिलाओं को कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो कमज़ोर, छोटी और कम बुद्धिमान होती हैं।' इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उन्हें मिलने वाला भत्ता भी बंद हो गया था।

कोलकाता की लॉ छात्रा मामले में टीएमसी नेताओं की टिप्पणियां निस्संदेह निंदनीय हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जानी चाहिए। ममता बनर्जी के सामने एक और चुनौती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार- हत्याकांड और उसके बाद देश भर में उपजा आक्रोश अभी भी यादों में ताजा है। निस्संदेह, केवल टिप्पणियों से पार्टी को अलग कर देना ही पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक जीवन में नारी सम्मान एवं जीवन-मूल्यों के खिलाफजाने वाले लोगों के लिये परिणाम तय होने चाहिए। अन्यथा समाज में ये संदेश जाएगा कि ऐसे कुत्सित प्रयासों के खिलाफकोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। किसी अपराध की रोकथाम अच्छे शासन की अनिवार्य शर्त बनना चाहिए लेकिन जब कोई अपराध होता है तो प्रभावी प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। टीएमसी दोनों ही मामलों में विफल प्रतीत होती है। ऐसे मामलों में अत्याचार करने वालों की ही भांति अत्याचार का समर्थन करने वाले दोषी है। अत्याचारियों के लिये ही त्वरित न्याय और सख्त सजा जरूरी है लेकिन जन-प्रतिनिधि की निर्लज्ज बयानबाजी भी अपराध के दायरे में होनी चाहिए। आजीवन शोषण, दमन, अत्याचार, अवांछित बर्ताव और अपमान की शिकार रही भारतीय नारी को अब ऐसे और नये-नये तरीकों से कब तक जहर के घूंट पीने को विवश होना होगा। अत्यंत विवशता और निरीहता से देख रही है वह यह क्रूर अपमान, यह वीभत्स अनादर, यह दूषित व्यवहार एवं संकुचित न्याय। न्याय एवं राजनीति की चौखट पर भी उसके साथ दोयम दर्जा एवं दुराग्रहपूर्ण सोच बदलना सर्वोच्च प्राथमिकता हो। यदि हम सच में नारी के अस्तित्व एवं अस्मिता को सम्मान देना चाहते हैं तो ईमानदार स्वीकारोक्ति, पड़ताल एवं निष्पक्ष न्याय से ही यह संभव होगा।

क्यों नहीं पहुंच पातीं सरकारें घरों की दहलीज तक?

संजीव कुमार मिश्र

भारतीय राजनीति में महिलाओं के सशक्तीकरण की बातें खूब होती हैं। चुनावी घोषणापत्रों में उनके लिए वादे भी किए जाते हैं, परंतु चुनाव बीतते ही वायदों पर धूल की परत जम जाती है। शायद ही कोई जनप्रतिनिधि उनके दुख-दर्द को सुनने, उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए घर की दहलीज तक जाता हो?

यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं ने जिया है। लेकिन तारीफकरनी होगी बिहार की जिसने इस परिपाटी को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसा प्रदेश, जिसने दशकों तक महिलाओं को पुरुषों के निर्देशों पर मताधिकार का प्रयोग करते देखा, आज वही महिला सशक्तीकरण की एक ऐसी नई इबारत लिख रहा है, जो देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुकी है।

इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव 'महिला संवाद' कार्यक्रम है, जिसे विगत 18 अप्रैल से प्रदेश में ग्राम स्तर पर शुरू किया गया। यह पहल केवल एक सरकारी कवायद नहीं, बल्कि महिलाओं को केंद्र में रखकर सामाजिक बदलाव को गति देने का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्यक्रम प्रदेश की बेटियों, माताओं और बहनों की आवाज़ को गंभीरता से सुनने, समझने और भविष्य की नीतिगत व प्रशासनिक पहलों को आकार देने का एक महत्त्वपूर्ण मंच बन गया है।

यह संतोष का विषय है कि अब तक 38 जिलों में 52,468 महिला संवाद कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो चुका है, जिसमें कुल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह संख्या इस बात का भी जीवंत प्रमाण है कि प्रदेश की महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने और सरकार से सीधे जुड़ने को लेकर कितनी उत्सुक और जागरूक हैं। दरभंगा से लेकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, नालंदा और वैशाली तक, हर जगह महिलाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने नीति-निर्माताओं को यह समझने का अवसर दिया है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे किन प्राथमिकताओं के साथ कदम बढ़ाए जाएं।

महिला संवाद की यह पृष्ठभूमि आकस्मिक नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सबसे पहले, लड़कियों में शिक्षा की अलख जगाने पर ज़ोर दिया गया। जहां वर्ष 2000 के आसपास बिहार में लड़कियाँ सरकारी स्कूलों में कम जाती थीं, वहीं वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस योजना ने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिससे वे दूर-दराज के गांवों से भी साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने लगीं। इसकी सफलता ने देश के अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए। वर्ष 2013 से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। 2016 से सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है, और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तो 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त किया गया है।

महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन में 'जीविका' स्वयं सहायता समूह का गठन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर शुरू की गई 'जीविका' ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा इन महिलाओं को दिया गया 'जीविका दीदी' नाम आज एक पहचान बन चुका है।

वर्तमान में, बिहार में 10 लाख 64 हजार स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक जीविका दीदियाँ जुड़ी हैं। जीविका से जुड़कर ये महिलाएं लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर अपने और अपने समुदाय के जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं।

महिला संवाद: भविष्य के विकास का रोडमैप- 'महिला संवाद' कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं ने कई महत्त्वपूर्ण और व्यवहारिक मांगें रखी हैं, जो उनकी दूरदृष्टि और आकांक्षाओं को दर्शाती हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग स्वरोजगार से जुड़ी है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के लिए सस्ते ब्याज दरों पर ऋण और 'जीविका दीदी की रसोई' व 'जीविका दीदी हाट' जैसी पहल शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर राइस मिलों की स्थापना, वेजिटेबल मार्ट, किसान सम्मान निधि में वृद्धि और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की मांगें भी मुखरता से उठी हैं।

बुनियादी सुविधाओं के लिए 'जीविका भवन', लाइब्रेरी और पंचायत स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं की मांग की गई है। सामाजिक सुधारों में शराबबंदी की तर्ज पर गुटखा, सिगरेट और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध, और सुरक्षा के लिए महिला पुलिस चौकी, हेल्प डेस्क तथा प्रखंड स्तर पर महिला थाना बनाने की मांगें भी प्रमुखता से रखी गई हैं। यह आशा की जाती है कि सरकार इन मांगों पर शीघ्रता से विचार कर अपेक्षित निर्णय लेगी।

यह संतोषजनक है कि बिहार सरकार की नीतियों और योजनाओं के कारण प्रदेश में महिला सशक्तीकरण का एक स्वर्णिम दौर शुरू हुआ है। 2005 से पूर्व और उसके बाद बिहार में आए इस सकारात्मक बदलाव को आज हर स्तर पर देखा और महसूस किया जा रहा है। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं: 93.11त्न महिलाएं आज खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, 91.73त्न घरों में घरेलू हिंसा कम हुई है, और 87.75त्न महिलाएं खुद को आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत मानती हैं।

आज बिहार में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी लगन और मेहनत से अपना मुकाम बना रही हैं। यह बदलता बिहार है, जहाँ की बेटियां अब सिर्फ घर की चौखट के भीतर नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन और नीति-निर्माण में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विकसित बिहार के निर्माण में महिलाओं की यह बढ़ती भागीदारी न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि जब महिलाओं को अवसर और मंच मिलता है, तो वे न केवल अपनी बल्कि पूरे समाज की तकदीर बदलने की क्षमता रखती हैं।

देश में 1975 का आपातकाल संविधान की अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था

अजय दीक्षित

पचास साल पूरे हो गए देश में आपातकाल लगाने के जो 25 जून 1975 का तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति जनाब फकरुद्दीन अली अहमद ने संवैधानिक रूप से लगाया था। और कारण था श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इतीफा देने के बजाय यह रास्ता सत्ता में बने रहने के लिए चुना था क्योंकि उनके रायबरेली संसदीय चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस सिन्हा ने गैर संवैधानिक मान कर अवैध घोषित कर दिया था। हालांकि अलाहाबाद हाइकोर्ट ने स्व श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। लेकिन तत्कालीन विपक्ष ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की मांग की थी लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व श्रीमती इंदिरा ने रात्रि के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर संविधान की अनुच्छेद 352 के सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन राष्ट्रपति फकुरद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगा दिया और नागरिकों के मौलिक अधिकार पर रोक लगाने का कार्य किया।इतना ही नहीं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेई, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, राजनरायन,सहित पूरे भारत के विपक्ष को रात ही जेल भेज दिया।

उत्तर भारत में पूरी जेले नेताओं, कार्यकर्ताओं, और अन्य से भर गईं। 19 महीने तक उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वोत्तर, राज्यों, बिहार, पश्चिमी बंगाल,के राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव सही , विधि सम्मत माना और अल्लाहवाद हाइकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया।

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, संस्थानों को चोट पहुंची।सबसे अधिक वे पीड़ित रहे जो जेल में बंद थे और उनके परिवारों को आपातकाल की तृष्णा झेलनी पड़ी।तब भारत को आजाद हुए मात्र 28 साल हुए थे लोगो को भूखे पेट रहना पड़ा कुछ लोगों ने मजदूरी कर काम चला या।उनकी महिलाओं पर तो संकट ही गया। दूसरी ओर इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी देश को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे। अनुसासन तो आदमी तब करेगा जब खाना खाने को दाने हो लोगों को नौकरशाही ने तब बहुत परेशान किया।

पुलिस स्टेशनों में ग्रामीण एक एक सप्ताह तक इस लिए बैठे रहते थे कि उनसे धन की मांग हो रही थी।आवाज उठाने वालों को मीसा में बंद कर दिया जाता था।कुल मिलाकर ब्रिटिश रुल लौट आया था। अखबार,अन्य प्रकाशन होने वाली सामग्री पर सेंसरशिप लगी थी। डंडे के डर से रेलगाड़ियां, अस्पताल समय पर कार्य करने लगे लेकिन वह सब ढकोसला था।

कहीं आप भी सनस्क्रीन लगाते समय तो नहीं करते ये गलतियां

गर्मियों का मौसम हो या मानसून का महीना, स्किन को डैमेज से बचाने के लिए चेहरे पर सनस्क्रीन को अप्लाई करना जरूरी है। स्किन को खतरनाक यूवी किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। लेकिन कई बार त्वचा पर सनस्क्रीन लगाने से मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करते समय कुछ गलतियां कर रहे हों। चलिए आज हम आपको सनस्क्रीन लगाने से जुड़ी कुछ गलतियों के बारे में बताने जा रहें, जिनके बारे में शायद आप भी न जानते हों।

कम सनस्क्रीन लगाना

सबसे आम गलतियों में से एक है कि सही मात्रा में सनस्क्रीन न लगाना। इसलिए त्वचा का जो हिस्सा एक्सपोजर में आता हो, उस पर सही मात्रा में सनस्क्रीन लगाएं। इससे एक्सपोजर वाला हिस्सा डैमेज होने से बचेगा।

चेहरे के कुछ हिस्सों पर सनस्क्रीन न लगाना

कान, गर्दन के पीछे, होंठ और पैरों के ऊपरी हिस्से पर अक्सर लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। इन जगहों पर सनबर्न का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए जब आप चेहरे पर सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हों, तो बॉडी के इन हिस्सों पर सनस्क्रीन भी लगाएं।

आधे घंटे पहले लगाएं सनस्क्रीन

सनस्क्रीन को धूप में निकलने से कम से कम 15-30 मिनट पहले लगाना चाहिए ताकि यह त्वचा में ठीक से अवशोषित हो सके और प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सके।

दोबारा न लगाना

अगर आप तैराकी कर रहे हैं, जिम में पसीना बहा रहे हैं तो हर दो घंटों में सनस्क्रीन दोबारा जरूर लगाएं। बहुत सारे लोग चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, जिससे उन्हें सन डैमेज से पूरी तरह से सुरक्षा नहीं मिल पाती है। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बादल के दिनों के दौरान सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसे मौसम में भी आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें।

एक्सपायरी डेट करें चेक

अपने सनस्क्रीन पर एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। एक्सपायरी डेट वाली सनस्क्रीन लगाने से स्किन को नुकसान हो सकता है। इसलिए इसे नियमित रूप से बदलना भी जरूरी है।

आसानी से नहीं सोता है बच्चा

ये टिप्स करें फॉलो

संकेतों पर ध्यान दें

बच्चे को गहरी नींद में सुलाने के लिए सबसे पहले उसके सोने का समय ध्यान में रखें। ऐसे में नींद आने पर बच्चे अक्सर आंखों को मसलने, रोने, उबासी लेने या चिड़चिड़ापन जैसे संकेत देते हैं। बच्चों के इन इशारों को समझकर आप उन्हें तुरंत सुला सकते हैं।

दूध पिलाना ना भूलें

छोटे बच्चों को सुलाने से पहले उन्हें स्तनपान अवश्य करवा दें। ऐसे में पेट भरा होने से बच्चों को जल्दी नींद आ जाती है। वहीं सोते समय बच्चों को भूख भी नहीं लगती है। जिससे बच्चे भरपूर नींद ले सकते हैं।

शांत कमरे में सुलाएं

बच्चों को शोर गुल वाली जगहों पर सुलाने की गलती बिल्कुल ना करें। इससे बच्चे गहरी नींद में नहीं सो पाएंगे। वहीं आवाज आने के कारण बच्चे अधूरी नींद में ही उठकर बैठ जाएंगे। इसलिए बच्चों को सुलाने के लिए शांत कमरे का चुनाव करें।

बच्चे के साथ में रहें

बच्चों को सुलाने के बाद पेरेंट्स अक्सर काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में कई बार बच्चे मच्छर काटने या डायपर गीला होने के कारण जाग जाते हैं। इसलिए सोते समय बच्चे के आसपास रहें और समय पर उसका डायपर जरूर चेंज कर दें।

सफाई का ध्यान रखें

नवजात शिशुओं को गंदी जगहों पर भी सुलाने से बचना चाहिए। इससे बच्चे को बैक्टीरियल इंफेक्शन, जलन, खुजली और अन्य परेशानी होने का डर रहता है। इसलिए बच्चे को हमेशा साफ जगह पर ही सुलाएं। जिससे बच्चों का हाईजीन मेंटेन रहता है।

लूज कपड़े पहनाएं

बच्चों को सुलाते समय टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहनाएं। इससे बच्चों को घबराहट महसूस होती है और बच्चे सही तरह से सो नहीं पाते हैं। ऐसे में बच्चों को सुलाने से पहले उन्हें हल्के और ढीले कपड़े पहना दें। जिससे बच्चे आराम की नींद ले सकेंगे।

ये संकेत बताते हैं कि आपका भाग्य खुलने वाला है

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी व्यक्ति का भाग्य खुलने वाला होता है तो, उसे कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत देखने में बहुत आम लग सकते हैं, लेकिन इनके मिलने पर व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं भाग्य खुलने के संकेत कौन से हैं। शकुन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कभी-कभी भाग्य खुलने से पहले व्यक्ति को कुछ संकेत मिलने लगते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको भाग्य बदलने से पहले मिल सकते हैं।

अगर आपको अपने घर के आसपास गाय का बार-बार दिखने लगे तो समझिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। इसके अलावा, अगर आपकी घर की छत पर कोयल का चहचहाना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में देवी-देवताओं के दर्शन होने लगें, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपका भाग्य बदलने वाला है। साथ ही, सपने में पूर्वजों का खुश दिख जाएं तो समझिए कि आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अगर आपको सपने में सफेद उल्लू दिख जाए, तो समझिए कि जल्द ही आपकी किस्मत चमकने वाली है।

सपने में सफेद उल्लू देखने का मतलब है कि आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आने वाली है और मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान हैं। शकुन शास्त्र के मुताबिक, अगर आपको सुबह उठने के तुरंत बाद मंदिर की घंटी, शंख या फिर भजन-कीर्तन की आवाज सुनाई देती है, तो एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। अगर आपकी छत पर अचानक मोर आ जाए, तो यह भाग्य खुलने का संकेत माना जाता है। छत पर मोर का आना ज्योतिष की दृष्टि से शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपकी किस्मत चमकने वाली है।

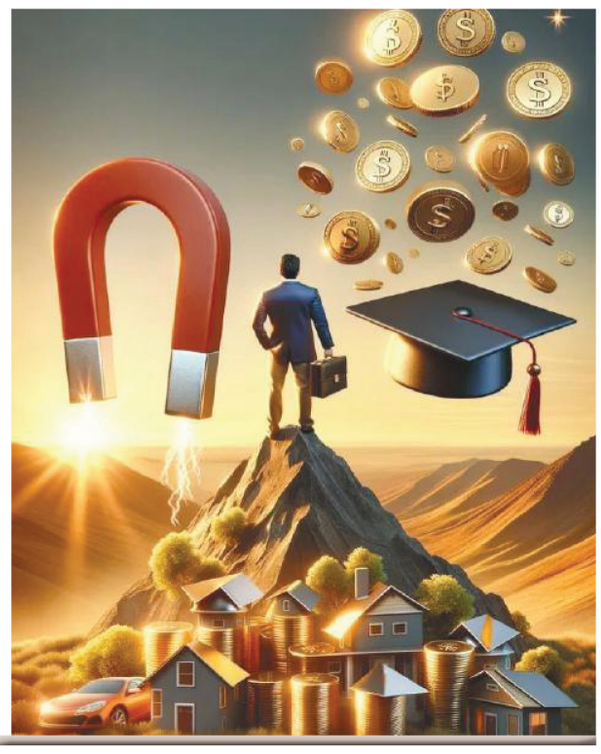

छीलकर न खाएं ये फ्रूट्स

सेहत को पहुंच सकता है नुकसान

फल हमारी डाइट का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन फलों को सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है।वहीं कई फलों को छिलके समेत खाया जाता है क्योंकि ऐसा न करने से उनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फलो के छिलकों में भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं।वैसे तो आजकल फलों पर केमिकल्स डाले जाते हैं इस कारण से लोग फलों का छिलका निकालकर खाते हैं।लेकिन हम यहां आपको बताएंगे कि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि वो कौन से फल हैं जिनको छीलकर नहीं खाना चाहिए?

सेब (Apple)

कई लोग का छिलका निकालकर खाते हैं लेकिन आपको बता दें कि सेब के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाया जाता है, इसलिए सेब को धोकर सीधे खा लेना चाहिए इसका छिलका छीलकर नहीं करना चाहिए।

चीकू (chiku)

चीकू का सेवन छिलके समेत किया जाता है। इसके छिलके में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स,आयरन पाया जाता है। इसलिए चीकू का सेवन छिलके समेत किया जा सकता है।

नाशपाती (Pear)

नाशपाती का सेवन हमेशा छिलके के साथ ही करना चाहिए।इसके छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। नाशपाती को छिलके समेत खाएंगे तो बॉडी को डायट्री फाइबर मिलेगा। नाशपाती को हमेशा बिना छीले ही खाना चाहिए।

अमरुद (Guava)

अमरूद का सेवन छिलके समेत कर सकते हैं। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, फाइबरस और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए अमरूद को कभी भी छीलकर नहीं खाना चाहिए। वहीं ध्यान रखें कि जुकाम या खांसी होने पर इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

कीवी (Kiwi)

कीवी का सेवन छिलके समेत करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कीवी के छिलके में फाइबर,फोलेट, विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं।इसलिए कीवी का सेवन छिलके सहित कराने चाहिए।

रात में सोने से पहले करें ये काम
वजन होगा तेजी से कम

आज के समय में हर दूसरा इंसान मोटापे का शिकार है। ऐसे में अगर आप भी डाइटिंग और घंटों में समय बिताने के बाद वजन कम नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां पर आपको कुछ आसान से काम बताएंगे जिन्हें करने के बाद आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। जी हां रात में सोने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए।

7 बजे के बाद डिनर

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रात में 7 बजे के बाद डिनर ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। बता दें रात में देर से खाना खाने से खाना ठीक से पच नहीं पाता है और मोटापा बढ़ने लगता है।

गर्म पानी पिएं

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डिनर के बाद ग्रीन टी या गर्म पानी जरूर पिएं।ऐसा करने से खाना आसानी से पच जाता है। वहीं ग्रीन टी से शरीर का मोटापा कम करने में मदद मिलती है।

अच्छी नींद लें

हमारी नींद और मोटापे के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको रोजाना रात में अच्छी नींद लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। जिससे वजन नहीं बढ़ेगा।

हल्दी वाला दूध पिएं

वजन कम करने के लिए हल्दी वाला दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें थर्मोजेनिक प्रॉप्रटीज होती है जिससे वट कम करने में मदद मिलती है।

रोज खाएं मखाना, इन बड़ी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा

मखाना आपकी सेहत के लिए बहत ही फायदेमंद होता है।जी हां बीपी,कोलेस्ट्रोल सहित कई बीमारियां ऐसी है जिसमें मखाना दवाई का काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मखाने में प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है।जिसकी वजह से यह आपकी सेहत के लिए हर तरह से फायदेमंद है। हम यहां आपको बताएंगे कि मखाना खाने के क्या लाभ होते है?

ब्लड शुगर लेवल

आजकल ज्यादातर लोग डायबिटीज की बीमापी से परेशान रहते हैं। ऐसे में मखाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मखाना खाने से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज के मरीज हैं तो आप मखाने का सेवन कर सकते हैं।

वजन कम करने में

मोटापे से परेशान लोगों के लिए मखाना काफी फायदेमंद हो सकता है।ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वजन कम करने वाले तत्व होते हैं। प्रोटीन और फाइबर होता है जो वजन घटाने में मददगार है।

एंटी एजिंग प्रॉपर्टी

मखाना में कई अमीनो एसिड होते हैं जिनमें एंटी-एजिंग प्रॉपर्टी मौजूद होती हैं। अगर आप रोजाना मखाने का सेवन करते हैं तो समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता है, ऐसा इसलिए क्योंक मखाना स्किन के लिए फायदेमंद होता है।

हार्ट हेल्थ

आजकल ज्यादातर लोग हार्ट से जुड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आप अपनी डाइट में मखाना शामिल कर सकते हैं। मखाना कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है।

न्यूट्रिएंट्स से भरपूर-

मखाने में की ऐसे तत्व होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें कैल्सियम,आयरन,और फास्फोरस होते हैं जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होते हैं।

कुर्ते को फैंसी तरीके से स्टिच करवाएं

सूट पहनती हैं और सोचती हैं कि आपका लुक बोरिंग है तो अपने इंडियन वियर को पहनना ना छोड़ें। बल्कि, अपने कुर्ते को फैंसी तरीके से स्टिच करवाएं। अगर आप हर बार वहीं एक जैसी नेकलाइन बनवाती हैं तो फ्रंट और बैक की इन ब्यूटीफुल और स्टनिंग दिखने वाली नेकलाइन को सिलवा लें। सब आपके बदले हुए अंदाज की तारीफ करेंगे।

वी नेकलाइन विद ट्विस्ट

सिंपल से कुर्ते को वी नेकलाइन डिजाइन के साथ स्टिच करवाना है तो फैब्रिक के बॉर्डर को वी शेप में स्टिच करवाएं। ये आपके प्लेन कुर्ते को डिजाइनर लुक देगा।

साइड कॉलर नेकलाइन

कुर्ते में कॉलर बनवाना चाहती हैं तो जैकेट डिजाइन के कॉलर को साइड करके स्टिच करवाएं। ये कुर्ते को बिल्कुल यूनिक और स्मार्ट लुक देगा।

ब्यूटीफुल एंब्रायडरी कॉलर नेकलाइन

फैब्रिक पर अगर एंब्रायडरी है तो उसे हाईलाइट करने के लिए कॉलर बनवाएं और इसे हटके लुक देने के लिए राउंड शेप दें। ये ब्यूटीफुल दिखेगा।

यूनिक डिजाइन नेकलाइन

कुर्ते के सिंपल से नेकलाइन को थोड़े से ट्विस्ट के साथ अलग-अलग डिजाइन दिया जा सकता है। फैब्रिक के इस्तेमाल से गले पर ये डिजाइन बनवा लें।

ड्रॉप बैक नेक

प्रिंटेड डिजाइन का कुर्ता है तो बैक पर इस तरह के ड्रॉप डिजाइन के साथ ऊपर की तरफ दो फैब्रिक के बटन को स्टिच करवाएं।

डायमंड शेप

कुर्ते का गला डिजाइनर सिलवाना है तो बैक पर इस तरह के डायमंड शेप को स्टिच करवा सकती हैं। ये ब्यूटीफुल दिखता है।

पाइपिंग लगवाएं

सूट सिलवा रही हैं तो बैक पर जब भी गले की डिजाइन कट करवाएं तो उसमे अपोजिट कलर की पाइपिंग करवाएं। जिससे कि डिजाइन हाइलाइट हो और ब्यूटीफुल दिखे।

सावन में इन कामों को करना है मना

सावन का महीना देवों के देव महादेव की आराधना करने के लिए समर्पित होता है. भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सावन अत्यंत पावन माना जाता है. यह महीना व्रत-उपवास के लिए खास माना गया है. साल 2025 में सावन की शुरुआत 11 जुलाई से होने वाली है. शिव भक्त इस पूरे महीने भोलेनाथ की पूजा-अर्चना में लीन रहते हैं. सावन के महीने में पूजा-पाठ के साथ कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन में कुछ काम करने से बचना चाहिए. अगर आप इन कार्यों को करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से वंचित रह सकते हैं.

बाल और दाढ़ी न कटवाएं : सावन में बाल या दाढ़ी कटवाना शुभ नहीं माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सावन में बाल या दाढ़ी कटवाने से कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा में कमी हो सकती है.

शरीर पर तेल न लगाएं : स्कंद पुराण के मुताबिक, सावन में शरीर या सिर पर तेल लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है. सावन के सोमवार के दिन शरीर पर तेल लगाना पूरी तरह वर्जित माना गया है. सावन में तेल के मालिश भी नहीं करनी चाहिए.

दही का सेवन न करें : सावन के महीने में दही खाना वर्जित माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, सावन में दही खाने से शुक्र दोष उत्पन्न हो सकता है. इसके अलावा, व्यक्ति को भाग्य का साथ भी नहीं मिलता है.

संक्षिप्त समाचार

व्यवसाय भीख मांगना, घर में हुई चोरी एक लाख

बिलासपुर (समय दर्शन)। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी ही व्हीलचेयर पर दो बोरी रखकर आया एक व्यक्ति सामान्य लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गया। बंधवा पारा के अंबेडकर आवास में रहने वाला इस व्यक्ति स्वयं बताया कि उसका पेसा भीख मांगना है और उसके घर से 1 लाख रुपए की चोरी हो गई। सो आवेदन देने आया है हमने जब उससे कहा कि संबंधित थाना क्यों नहीं जाते तब उसका जवाब चोर है साले था।

धमतरी पुलिस ने धारदार प्रतिबंधित हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल

ब्यूरों सैय्यदा मुनीज़ा हुसैनी धमतरी छत्तीसगढ़। धमतरी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने एक युवक को धारदार प्रतिबंधित हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराकर लोगों को डरा धमका रहा था। थाना सिटी कोतवाली पुलिस पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था, उसी दौरान कचहरी चौक के पास पुलिस को सूचना मिली कि एकलव्य खेल मैदान (इंडोर स्टेडियम) धमतरी के पास एक युवक लोहे का धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर अपना नाम टेमन डहरिया पिता घना राम डहरिया उम्र 21 वर्ष, निवासी सतनामीपारा, सदर रोड, नयापारा, राजिम, का रहने वाला बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक नग धारदार प्रतिबंधित लोहे का चाकू बरामद किया गया, जिसे गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त कर सीलबंद किया गया। आरोपी द्वारा प्रतिबंधित शस्त्र को अवैध रूप से सार्वजनिक स्थल पर रखकर आम जनता में भय और दहशत का माहौल उत्पन्न किया गया, जो कि भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत दंडनीय अपराध है। थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 162/2025 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया।
आरोपी का नाम-: टेमन डहरिया पिता घना राम डहरिया उम्र 21 वर्ष, निवासी सतनामीपारा, सदर रोड, नयापारा, राजिम, जिला रायपुर (छ.ग.)

25 हजार रुपये की लूट करने वाले दो फरार आरोपियों को कुरूद पुलिस ने गिरफ्तार, कर भेजा जेल

ब्यूरों सैय्यदा मुनीज़ा हुसैनी धमतरी छत्तीसगढ़। धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र में 25,000/- रुपये की लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो फरार आरोपियों को कुरूद पुलिस द्वारा सतत प्रयासों के फलस्वरूप गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार के कुशल दिशानिर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुरूद के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक राजेश जगत के नेतृत्व में की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण:* प्रार्थी रामेश्वर सतनामी, निवासी राखी, थाना कुरूद, ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 16 जून 2025 को अपने पुत्र कोमेश दास के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, कुरूद शाखा से ?25,000/- रुपये की नकद राशि निकालकर अपनी पैंट की जेब में रखकर पैदल सेलून की ओर जा रहा था। लगभग दोपहर 3:00 बजे के आसपास वह वृंदावन तालाब के पास, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पेशाब करने रुका, तभी तीन युवक ड्ड यज्ञ उर्फ जीवा दीवान, बंठा और धर्मेन्द्र -वहां पहुंचे और प्रार्थी को जबरन पकड़कर उसकी जेब से नकदी रकम लूट ली। विरोध करने पर आरोपियों ने पत्थर उठाकर मारपीट की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। प्रार्थी की सूचना पर थाना कुरूद में तत्काल अपराध क्रमांक 158/2025 धारा 309(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुरूद थाना पुलिस द्वारा तत्काल अलग-अलग टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ की गई। सतत सुरागरसी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मुख्य आरोपी यज्ञ कुमार दीवान उर्फ जीवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपराध में संलिप्तता स्वीकारते हुए बताया कि उसे लूट के बंटवारे में 8,000/- प्राप्त हुए थे। आरोपी की निशानदेही पर उक्त राशि गवाहों के समक्ष विधिवत रूप से जप्त की गई। आज दिनांक 17 जून 2025 को आरोपी यज्ञ कुमार दीवान उर्फ जीवा को 24 घंटे के अंदर ही पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसको न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया था । आज फरार दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

आरोपीगण का नाम-: धर्मेंद्र साहू,उर्फ चुंमन साहू,पिता विजय साहू,उम्र 18 वर्ष 7 माह,साकिन सिरसा चौक पचरी पारा कुरूद, थाना कुरूद,जिला धमतरी (छ.ग.), गौरव यादव उर्फ़ बनठा पिता त्रिभुवन यादव,उम्र 19 साल इंदिरा नगर कुरुद,थाना कुरूद,जिला धमतरी (छ.ग.)

जो पारे में पार्टी को नहीं जीता पाते, उन पर पार्टी को भीड़ जुटाना का विश्वास

मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष

बिलासपुर (समय दर्शन)। जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ आना है। कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है, और बैठकों का दौर जारी है। बैठकों की जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोगों को भी मिल रही है जिससे पार्टी के प्रति समर्पित नेता और कार्यकर्ताओं के बीच रोष है। मस्तूरी विकास खंड क्षेत्र के विधायक ने अपने ब्लॉक अध्यक्ष को इस बात की सूचना दी कि मस्तूरी क्षेत्र में संगठन की बैठकों का प्रभारी देवेंद्र सिंह को बनाया गया है। तभी से मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों के बीच असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। आम कार्यकर्ता भी अपने ब्लॉक अध्यक्ष से यह पूछ रहा है कि ऐसे प्रभारी महोदय जो अपने मोहल्ले के बूथ पर मतदान के दिन बैठने वाला नहीं ढूंढ पाते जिनके बुथ से 20 सालों में कांग्रेस नहीं जीत रही उनको मस्तूरी में प्रभार, आम कार्यकर्ता को नीचा दिखाना है। कुछ लोग यह भी कहते है कि बूथ नहीं जीता, वार्ड नहीं जीता वार्ड में भाजपा के प्रत्याशियों को इसलिए जीत मिलती है कि मोहल्ले के कांग्रेसी नेता पार्टी से ज़्यादा रिश्तेदारी पर ध्यान देते हैं। ऐसे नेता को मस्तूरी में ज़िम्मेदारी देना भविष्य में कांग्रेस की जड़ों को खोखला कर देगा। विस्तार से देखें तो मस्तूरी में एक समय जोगी कांग्रेस का संगठन बेहद मजबूत हो गया था और विधायक भाजपा का था। जब प्रदेश संगठन ने ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में नागेंद्र राय चेहरे को चुना तो धीरे-धीरे ब्लॉक में कांग्रेस का संगठन आकर लेता गया। विधानसभा चुनाव में दिलीप लहरिया को टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी की आंधी में भी संगठन ने अपने दम पर एक ऐसे चेहरे को चुनाव जिताया जिसके प्रति पर्याप्त नाराजगी थी। चुनाव जीतने के बाद विधायक इस संगठन को दत्ता दिखाते रहते हैं। जिसकी दम पर वे चुनाव जीते लोकसभा चुनाव के वक्त भी जीते हुए विधायक से ज्यादा मेहनत संगठन के पदाधिकारीयों ने कि कांग्रेस के युवा ब्रांड कन्हैया कुमार की कम समय पर सफल आमसभा ब्लॉक संगठन के कारण ही संभव हो पाई। स्थानीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी पार्टी जीत के लिए विधायक रोडा नहीं मानती। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को टारगेट करती है। मतदान के 24 घंटे पूर्व उनके विरुद्ध मामले कायम किये जाते हैं। देर रात न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में श्रोता लाने के लिए देवेंद्र जी को प्रभारी बनाना संगठन को कमजोर कर देने के समान है।

संकुल समन्वयक संघ सरायपाली के अध्यक्ष बने देवानंद नायक

नृपनिधी पाण्डेय सरायपाली (समय दर्शन)। संकुल समन्वयक संघ सरायपाली के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव सम्पन्न हुआ. जिसमें सर्वसम्मिति से सभी संकुल समन्वयकों द्वारा देवानंद नायक (संकुल समन्वयक केंदुढार) कों अध्यक्ष नियुक्त किया गया. जिसमें संकुल समन्वयक घनश्याम दास प्रस्तावक रहे एवं प्रभात मांझी समर्थक रहे. वही प्रमुख रूप से वरिष्ठ संकुल समन्वयक भोलानाथ नायक, पुरषोत्तम पटेल, किशोर पटेल, रविशंकर आचार्य, लाल भूषण पाढ़ी, सुशील चौधरी, कृष्णचन्द्र पटेल, जय नारायण पटेल, प्रभात मांझी, दुष्यन्त पटेल,

अरुण विशाल, ऋषि प्रधान, श्रवण प्रधान गिरधारी लाल पटेल, संजीत पात्रों, मुकेश बारीक़, पाल सिंह बंजारे, किशोर पंडा, कौशल प्रधान, घनश्याम दास उपस्थित रहे. इसके साथ ही 3 नए संकुल समन्वयक गिरधारी लाल पटेल, संजीत पात्रों और नवीन मिश्रा का अध्यक्ष देवानंद नायक के द्वारा स्वागत किया गया.

लायंस क्लब की अध्यक्ष आकांक्षा मिश्रा की टीम ने ली शपथ

दुर्ग (समय दर्शन)। लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उन्हें समारोह के मुख्य अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद्मश्री डॉ. पुखराज बाफना के मौजूदगी में शपथ अधिकारी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अमरजीत दत्ता द्वारा शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष आकांक्षा मिश्रा, सचिव हरमीत सिंह भाटिया, कोषाध्यक्ष अनिता तिवारी, उपाध्यक्ष महमूद हिरानी, पुरुषोत्तम टावरी, डॉ. राजू शारदा ने शपथ ग्रहण की और क्लब को ऊचाईयों में ले जाने बेहतर कार्य करने की अपनी मंशा व्यक्त की। समारोह में क्लब के दो नए सदस्य धनश्री मोड़क एवं जफर को भी शपथ दिलाई गई। लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद्मश्री डॉ. पुखराज बाफना थे। उन्होने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी। कार्यक्रम में शपथ अधिकारी का परिचय रूपिंदर कौर कालकेट एवं मुख्य अतिथि का परिचय डॉ. राजू शारदा ने दिया। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की पूर्व अध्यक्ष सुमन पांडे द्वारा

स्वागत भाषण में वर्षभर संस्था द्वारा किए गए कार्यों से अतिथियों को अवगत कराया गया और सहयोग के लिए लायन सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। पूर्व सचिव रश्मि अग्रवाल ने सेवा परमोधर्म की भावना के साथ क्लब के गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। जिसकी सदन ने सराहना की। एमजेएफ बृजमोहन खंडेलवाल द्वारा संस्था के स्थायी प्रोजेक्ट मानवता शाला (विशेष बच्चों के लिए विद्यालय) की जानकारी सदन को दी गई। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संतोष राय ने किया। समारोह में पीएमजेएफ सतीष चंद सुराना, ज्ञानचंद पाटनी, एमजेएफ डॉ. रौनक जमाल, जरीना जमाल, कैलाश बरमेचा, मंजू बरमेचा,मृदुला रोजिन्दर, एसपीएस दुलई, अमर सिंह गुप्ता, शंकरलाल अग्रवाल, भाग्यश्री मोड़क , सुनीता दीवान, शिल्पा पांडे, अनिमेष मिश्रा, रंजना मिश्रा, आकांक्षा तिवारी, ओमप्रकाश तिवारी, अंकिता तिवारी, श्रुति तिवारी के अलावा अन्य लायन सदस्य शामिल हुए।

नौकरी के नाम पर 12 लाख झटके और पूरे लेन-देन को जमीन में उलझाया

आवेदक छोटे कुमार तीन बार दे चुका आवेदन

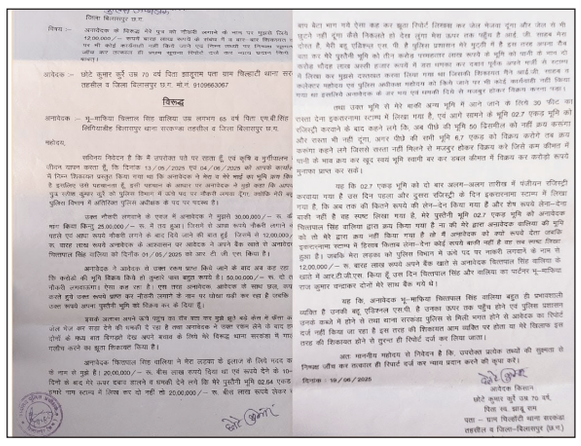

बिलासपुर (समय दर्शन)। छोटे कुमार कुर्रे निवासी ग्राम पंचायत चिल्हाटी ने बिलासपुर पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक दोनों को इस आशय की शिकायत की है कि चित्ताल सिंह वालिया ने पहले उनकी भूमि खरीदी पहचान होने के बाद पुलिस विभाग में नौकरी लगवा देने का भरोसा दिया और 25 लाख रुपए में से 12 लाख रुपया ले लिया। 12 लाख का यह लेन-देन श्री कुर्रे की शिकायत के अनुसार 1 मई 2025 को आरटीजीएस के माध्यम से हुआ। आवेदक का कहना है कि नौकरी लगवाने का पूरा काम पहले 25 लाख में तय हुआ था। पहली किस्त ले लेने के बाद वालिया ने नौकरी के लिए 50 लाख की बात कही और पूरे मामले को जमीन

की खरीदी बिक्री से जोड़ दिया। छोटे कुमार का कहना है कि वालिया ऊंची पहुंच वाला है और अपने रिश्तेदारों की ऊंची पहुंच का हवाला देकर डरता धमकता भी है। और उनकी पुश्तैनी जमीन को बहुत ही सस्ते दाम पर बेचने के लिए मजबूर करता है। एक बार वे उसे जमीन बिक्री कर चुके हैं। छोटे कुमार का कहना है कि 19 जून 2025 के पूर्व वे विभाग में दो बार और लिखित शिकायत किये है। पर विभाग में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कुर्रे और उनके पुत्र खेती और मुर्गी पालन कर के जीवन यापन करते हैं। कृषि भूमि के पैतृक उत्तराधिकारी हैं इस कारण भी भूमि क्रय-विक्रय करने वाले दलाल उनके ऊपर दबाव बनाते रहते हैं।

14 खिलाड़ियों को मिला ब्लैक बेल्ट व 51को कलर बेल्ट

रायपुर (समय दर्शन)। सीको काई कराते इंटरनेशनल रायपुर द्वारा पिछले महिने काफ क्लब के विभिन्न ब्रांच में बेल्ट परीक्षा ली गयी जिसका परिणाम शतप्रतिशत रहा जिसमें 14 ब्लैक बेल्ट एवं 51 कलर बेल्ट । खिलाड़ियों को दिया गया । सर्टिफिकेट का कार्यक्रम रायपुर प्रेस क्लब में रखा गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संजय शर्मा (ए.आई.जी. ट्रेफीक) और अध्यक्षता प्रफुल्ल ठाकुर (अध्यक्ष रायपुर प्रेस क्लब) विशेष अतिथि संदीप अग्रवाल (गोमती एग्रो इंड), श्रीमती सुजाता झारखण्डी (प्रिंसिपल रिटायर्ड), श्रीमती राधिका महेश्वरी व रेशी तुलसीराम सपहा (सीको काई प्रमुख रायपुर, काफकलब संस्थापक) व संजीव सिन्हा (काफ क्लब रायपुर प्रभारी) के द्वारा खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरीत किया गया।

इस मौके पर प्रेस क्लब के सचिव महोदय कोषाध्यक्ष एवं सभी पत्रकार मौजूद रहे।
इस अवसर पर खिलाड़ियों द्वारा कराते का प्रदर्शन किया गया

ब्लेक बेल्ट प्राप्त खिलाड़ी - शिवम प्रशांत, काजल कुर्रे, दीपक तारक, वंशिखा मोदी, काजल पुरैना, चैतन्य यदु, मयंक देवांगन, युवराज पुरेना, सागर भक्त सिन्हा, अपूर्वा बाजपेयी, विन्शी विक्टर, अंजलीना जॉनसन, अभिज्ञान तिवारी, दीक्षा रमानी

कलर बेल्ट प्राप्त खिलाड़ी - मोक्ष तारक, प्रणव ध्रुव, अद्विका नथानी, नाईशा कोहली, पियुष साहु, रुद्रांश गुप्ता, सर्नग्य, खुशी सिंग, भाविका, आध्या साहू, हर्षित, ट्रींसी, अलिषा, सिदिघी, देवेन्द्र निषाद, लिलिमा, राघवी, गौरव, मौलिशा रिशब, ज्योषिता, सालोम, रुत्वी, रुद्र, वी. सीजू, आरोही, आरातिका, गीतिका, अरनव, हर्षा, गैलिना, श्रीमयी, युतिका, ट्विंकल ।

इस अवसर पर - सेन्सेई आदित्य तिवारी, सेन्सेई आशीष शर्मा, सेन्सेई जयेश सपहा, सेन्सेई विपलव प्रशांत एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उपरोका जानकारी रेंशी तुलसीराम सपहा ने दी

डीएमएफ फंड का दुरूपयोग :मरीजों का जीवन दांव पर : आपातकाल मे देरी जानलेवा साबित

(डी एम एफ) फंड रुकने से स्वास्थ्य विभाग मे विकास कार्यों व स्वास्थ्य सेवाओं की रफ्तार धीमी-विमल सलाम

दंतेवाड़ा (समय दर्शन)। जिला में स्वास्थ्य विभाग (डीएमएफ) फंड रुक गया है जिसके चलते कई कामकाज में रोड़ा आ गया है। फंड के आभाव में निर्माण सहित स्वास्थ्य सेवाओं कि रफ्तार थम गई है। प्रशासन द्वारा फंड नहीं आने पर। स्वास्थ्य विभाग कि हालत बहुत ही बुरी है। ऐसा ही रहा तो विभाग कि स्तिथि बहुत ही खराब होगी।इससे मरीजों व कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।जिला कांग्रेस महामंत्री विमल सालम ने कहा विभाग को(डीएमएफ) फंड का समय पर नहीं मिलने पर वेतन वृद्धि और वेतन न मिलने पर लगातार डाक्टर और कर्मचारी छोड़कर जा रहे है।वही वेतन और वेतनवृद्धि नहीं मिलने से परेशान जिला अस्पताल के अब तक 2 सर्जन भी नौकरी छोड़ चले गए है।अचानक कोई अनहोनी हो जाए या कोई दुर्घटना हो तो मरीज का समय पर इलाज और सर्जरी न होने पर जान भी गंवाना पड़ सकता है।इधर सभी प्रकार के इंस्ट्रुमेंट और दवाइयों कि कमी से भी मरीज इधर-उधर भटकने पर मजबूर हैं। (जिला खनिज न्यास) फंड का उपयोग आपातकालीन और आवश्यक चिकित्सा सामग्री प्रदान करने में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मरीजों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ और जनता के साथ धोखा एक गंभीर मुद्दा है। जिला अस्पताल में बजट की कमी, आपातकालीन सामानों और दवाइयों की कमी जैसी समस्याएं जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही हैं।

छ्रस्न्न फंड का पैसा जनता के कल्याण के लिए है, न कि प्रशासन की जेब में रखने के लिए।जिला अस्पताल में दवाइयों और आपातकालीन सामानों की

कमी क्यों? सरकार और प्रशासन तुरंत छ्रस्न्न फंड से अस्पताल को बजट उपलब्ध कराए, वरना जनता सड़कों पर उतरेगी।दंतेवाड़ा में छ्रस्न्न फंड का करोड़ों रुपये जमा है, फिर भी जिला अस्पताल में मरीजों को दवाइयां और जरूरी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? यह जनता के साथ विश्वासघात है। हमारी मांग है कि छ्रस्न्न फंड का उपयोग तुरंत अस्पताल की बेहतरी के लिए हो। जिला प्रशासन और सरकार छ्रस्न्न फंड को अपने मनमाने तरीके से खर्च कर रही है, जबकि जिला अस्पताल में मरीज बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। छ्रस्न्न फंड से स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए।दंतेवाड़ा का जिला अस्पताल मरीजों के लिए आशा का केंद्र होना चाहिए, न कि लापरवाही का अड्डा! छ्रस्न्न फंड का पैसा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्यों नहीं? हमारी मांग है कि तुरंत बजट आवंटन हो, वरना जनता जवाब मांगेगी छ्रस्न्न फंड का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों की जनता का कल्याण के लिए है। फिर क्यों जिला अस्पताल में मरीजों को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है? हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि छ्रस्न्न फंड का दुरुपयोग बंद हो और अस्पताल को तुरंत संसाधन मुहैया कराए जाएं जब छ्रस्न्न फंड में करोड़ों रुपये उपलब्ध हैं, तो जिला अस्पताल में दवाइयों और आपातकालीन सामानों की कमी क्यों? यह जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार और प्रशासन जागे, छ्रस्न्न फंड से अस्पताल को तुरंत बजट पहुंचाएं। छ्रस्न्न फंड का गठन खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए किया

गया है,यदि छ्रस्न्न फंड अब जिला अस्पताल को नहीं दिया जा रहा है, तो यह नियमों का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि छ्रस्न्न नियमों के तहत कम से कम 60त्न फंड का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, और पेयजल जैसे सेवाओं के लिए होता है।जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में डीएमएफ फंड का सही उपयोग न होने से आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। यह गंभीर लापरवाही न केवल मरीजों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है, बल्कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर भी सवाल उठा रही है।खनिज न्यास का पैसा जनकल्याण के लिए है, न कि कागजों में सिमटने के लिए। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों को मूलभूत आपातकालीन सामग्री न मिलना प्रशासन की विफलता को दर्शाता है।समय पर दवाइयां और उपकरण न मिलने से मरीजों की जान जोखिम में है। डीएमएफ फंड का तत्काल और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।सरकार भले ही स्वास्थ्य सुधार की बात करे, लेकिन दंतेवाड़ा जिला अस्पताल की स्थिति बताती है कि डीएमएफ फंड का लाभ मरीजों तक नहीं पहुंच रहा। यह जनता के साथ विश्वासघात है।डीएमएफ फंड के गलत प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मरीजों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

खबर-खास

अपूर्व डेगन अभिनीत चार शॉर्ट फिल्मों को हंगामा ओटीटी ने रायपुर में आरएस1 में लॉन्च किया

रायपुर (समय दर्शन)। फिल्मीकैंडी एंड यूनिटी प्रोडक्शन एलएलपी ने आज चार प्रभावशाली शॉर्ट फिल्मों के रिलीज़ की घोषणा की है। ये चारों फिल्में इंस्टेंट लोन, फैमिली बॉय, ए कप ऑफ कॉफी, और झुनझुना – समाजिक मुद्दों पर आधारित हैं और अब केवल हंगामा ओटीटी पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही हंगामा ओटीटी ने रायपुर के दर्शकों के लिए एक विशेष ऑफर लॉन्च किया है आरएस1 में एक महीने का अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन। इस पहल का उद्देश्य अच्छे कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना और रायपुर के उभरते कलाकार अपुरव डेगन जैसे टैलेंट को प्रमोट करना है। इन कूपनों को आप रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित होते हुए देखेंगे। जैसे मरीन ड्राइव, कटोरा तालाब, एन. आई. टी. चोपाटी, पंडरी और शंकर नगर।

घोषणा आज रायपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहाँ कलाकार अपूर्व डेगन, निर्देशक खुशबू झा, और निर्माता हर्ष टोगानी उपस्थित थे।चारों शॉर्ट फिल्में आज के दौर से जुड़े अहम सामाजिक मुद्दों पर आधारित हैं।1

इंस्टेंट लोन – यह फिल्म युवाओं को आसानी से मिलने वाले लोन के खतरों के प्रति आगाह करती है। यह दिखाती है कि कैसे ये लोन बड़ी परेशानी और कर्ज में फँसा सकते हैं। निर्देशक खुशबू झा के अनुसार, यह फिल्म युवाओं और उनके माता-पिता के लिए एक वेक-अप कॉल है।

सैमसंग ने भारत में अपने 2025 बीस्पोओक एआई एप्लागयंसेज को लॉन्च किया, नए बीस्पोक एआई लॉन्ड्री कॉम्बो को भी पेश किया

गुरुग्राम: सैमसंग, भारत के सबसे बड़ेकंज्यूमिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, ने अपनी 2025 बीस्पोक एआई एप्ला यंसेज रेंज को लॉन्च किया है। इसरेंज में चार मुख्य लाभमिलते हैं। इसे इस्ते्माल करना व देखभाल करना बेहदआसान है, ये बचत करने के साथ ही पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये उपकरण सैमसंग के नए एआई होम स्क्रीन, बिक्सबी वॉयस असिस्टेंट के साथ बातचीत, सैमसंग नॉक्स सुरक्षा, और स्मार्टथिंग्स कनेक्टिविटी से चलते हैं। ये आधुनिक भारतीय घरों के लिए व्यक्तिगत, बिजली की बचत करने वाले, और सुरक्षित स्मार्ट होम समाधान देते हैं।

बीस्पोक एआई लाइन-अप चार मुख्य मूल्यों पर आधारित है जो उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाते हैं: आसान, बचत, देखभाल और सुरक्षित।

आसान: बीस्पोइक एआई उपकरण एआई होम, बिक्सबी, और स्मार्टथिंग्स की मदद से आपके रोज़मर्रा के कामों को अपने आप आसान बनाते हैं। एआई होम आपके काम को ऑटोमैटिक करता है, जैसे कि घर के उपकरणों को दूर से नियंत्रित करना या उनकी रीयल-टाइम जानकारी लेना। बिक्सबी आपको उपकरणों के बारे में सवाल पूछने और आसान, बातचीत जैसे वॉयस कमांड से उन्हें चलाने की सुविधा देता है, बिना फोन या स्पीकर की ज़रूरत के।

बचत: बीस्पोरक एआई उपकरण बिजली और समय दोनों की बचत करते हैं। एआई एनर्जी मोड बिजली की खपत को प्रबंधित करने में मदद करता है। रेफ्रिजरेटर में एआई विज़न इनसाइड खाने-पीने की चीजों और उनकी एक्सदपायरी डेट को ट्रैक करता है, बर्बादी से बचने के लिए रेसिपी सुझाता है। बीस्पोोक एआई लॉन्ड्री कॉम्बोइ और टॉप लोड वाशर में एआई वॉश फीचर मिट्टी के स्तर और लोड प्रकार के आधार पर साइकल को अनुकूलित करता है, जिससे समय और पानी की बचत होती है।

देखभाल: बिक्सबी उपकरणों की देखभाल और मेंटेनेंस अलर्ट में सहायता करता है, जबकि स्मार्टथिंग्स तीसरे पक्ष के उपकरणों के माध्यम से गति, धुआं या रिसाव का पता लगने पर सूचनाएं भेजता है। बीस्पो्क एआई निष्क्रियता अलर्ट जैसे फीचर्स के साथ मानसिक शांति सुनिश्चित करता है, जो परिवारों को दूर से आश्वस्त करता है।

सुरक्षित: सैमसंग नॉक्स उपकरणों और स्मार्टफोन्स पर विज़ुअलाइज़्ड डैशबोर्ड के साथ आला दर्जे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बीस्पोणक एआई फैमिली हब और बीस्पोक एआई लॉन्ड्री कॉम्बो सहित पांच सैमसंग उत्पादों को यूएल सॉल्यूशंस के आईओटीसिक्योरिटी रेटिंग्स से 'डायमंड' लेवल का सत्यापन मिला है।

दो दिनों में तीन आरोपी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

आरोपियों से 14.390 बल्क लीटर अवैध शराब और बुलेट मोटर सायकल जब्त।

कवर्धा (समय दर्शन)। पुलिस ने दो दिनों में तीन आरोपियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफ्लता पाई है। आरोपियों से पुलिस ने 14.390 बल्क लीटर अवैध शराब और बुलेट मोटर सायकल भी जब्त किया है।

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, पंकज पटेल एवं उप पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना कवर्धा में थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। अभियान के तहत 29 एवं 30 जून को तीन अलग-अलग स्थानों से अवैध देशी शराब जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

पुलिस ने बताया कि अपराध क्रमांक 280/2025 के तहत गिरफ्तार आरोपियों में 1. पंकज सोनी पिता प्रमोद सोनी, 22 वर्ष, पुराना कचहरी पारा, थाना कवर्धा, 2. अर्पित श्रीवास्तव पिता विमल श्रीवास्तव, 22 वर्ष, शीतला मंदिर लाइन, थाना

कवर्धा, इन दोनों आरोपियों से कुल 31 पौवा देशी प्लेन मदिरा (कुल मात्रा 5.580 बल्क लीटर) तथा एक नीले रंग की बुलेट मोटरसायकल (क्रमांक सीजी 11- एएस -0559) जब्त की गई। जप्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत ?92,480 बताई गई है। अपराध क्रमांक 282/2025 में आरोपी मनोज बंजारे पिता मेलाराम बंजारे, 30 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 01, रामनगर, थाना कवर्धा, इसके पास से 32 पौवा देशी प्लेन मदिरा (कुल मात्रा 5.750 बल्क लीटर) जब्त की गई। अनुमानित कीमत 2,560 बताई गई है।

अपराध क्रमांक 283/2025 के आरोपी संतानु टंडन पिता रेशम टंडन, उम्र 37 वर्ष, निवासी झलका, थाना कवर्धा, इसके कब्जे से 16 पौवा रोमियो देशी प्लेन मदिरा और 16 पौवा शोले मसाला मदिरा (कुल 5.760 बल्क लीटर) एवं नगद 360/- जब्त किए गए। कुल कीमत 3,240/- तीनों सभी मामलों में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और उनके नेटवर्क की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

जिला कबीरधाम पुलिस की यह कार्रवाई एक सख्त संदेश है कि अब जिले में अवैध शराब या नशे के किसी भी कारोबार के लिए कोई जगह नहीं है। कबीरधाम पुलिस पूरी सतर्कता, निगरानी और कड़े रवैये के साथ ऐसे अवैध धंधों पर लगातार शिकंजा कस रही है। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधियों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। यह स्पष्ट रूप से चेतावनी हैकृ जिले में नशे का अवैध व्यापार करने वालों की अब खैर नहीं। हर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस आमजन से भी अपील करती है कि यदि आपके आसपास कहीं भी अवैध शराब या नशे का कारोबार होता दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

दिल्ली पब्लिक स्कूल कवर्धा में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने हुए विविध आयोजन

कवर्धा (समय दर्शन)। दिल्ली पब्लिक स्कूल कवर्धा में 28 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु थीम इंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन निर्धारित की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रीन हाउस के विद्यार्थियों द्वारा प्रभावशाली विशेष प्रार्थना सभा प्रस्तुत की गई।

सभा में विद्यार्थियों ने प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्परिणामों को दर्शाते हुए एक लघु नाटक प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों ने विषय से संबंधित अंग्रेज़ी भाषण, कविता पाठ, तथा ग्रीन प्लेज (हरित संकल्प) के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

साथ ही विद्यालय में सीसीए के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को समाज से जोड़ने हेतु शैक्षणिक भ्रमण भी आयोजित किया गया। कक्षा 6 के छात्र-छात्राओं ने स्थानीय डाकघर का भ्रमण कर वहाँ की कार्यप्रणाली की जानकारी ली।

कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने राइस मिल (धान प्रसंस्करण इकाई) जाकर धान से चावल बनने की प्रक्रिया को देखा। कक्षा 8 के छात्रों ने ग्राम पंचायत कार्यालय का दौरा कर पंचायत की योजनाओं एवं प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा आयोजित इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता के साथ-साथ सामाजिक और प्रशासनिक ज्ञान को बढ़ाना था।

विद्यालय की प्राचार्या ने सभी विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया।

आयुक्त ने जर्जर अटल आवासों का निरीक्षण कर नये आवास के लिए आवेदन करने निर्देशित किए

भिलाईनगर (समय दर्शन)। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रं. 02 वैशाली नगर क्षेत्र का आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय निरीक्षण करने पहुंचे। वार्ड क्रं. 23 घॉसीदास नगर में कई वर्षो पहले वाम्बे आवास, अटल आवास एवं रशने आवास का निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में पुरी तरह से जर्जर हो गया है। उन मकानों का प्लास्टर टूट-टूट कर गिर रहा है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। उन आवासों में सैकड़ो परिवार अभी भी निवास कर रहे है, जिन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित नये आवासों के लिए आवेदन कराने जोन आयुक्त येशा लहरे एवं कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा को निर्देशित किया गया। साथ ही आवासों के पुर्ननिर्माण हेतु विशेष योजना के तहत शासन को प्रस्ताव

भेजने निर्देशित किया गया। वार्ड क्रं. 21 हेतु 81 लाख व वार्ड 23 के लिए 66 लाख लागत से रोड निर्माण हेतु मुख्यमंत्री नगरोथान योजना अंतर्गत प्रस्तावित रोड का निरीक्षण किये। रोड निर्माण हेतु पूर्व में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है, स्वीकृति पश्चात रोड निर्माण कराया जाएगा। बुद्व विहार में नाला साफ-सफाई कार्य का अवलोकन किये और कार्य करने वाले कर्मचारियो को ग्लब्ल, मास्क एवं गमबुट पहन कर साफ-सफाई कराने जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा को निर्देशित किये। कुरूद चौंक अमृत मिशन उद्यान का संधारण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें शोभायमान पौधे एवं कारपेट घॉस लगाकर अन्य आवश्यक कार्य कराने उप अभियंता अर्पित बंजारे को निर्देशित किये।

नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब अन्य विभागों में भी मिल सकेगी अनुकम्पा नियुक्ति

शहीदों के परिजनों को मिलेगा विभाग चुनने का विकल्प

कवर्धा (समय दर्शन)। राज्य शासन ने नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया है। पिछले दिनों मंत्रिपरिषद ने एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन को मंजूरी दी है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मानवीय निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्यायसंगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों की इस मांग को हमने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री श्री साय की

अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि इस संशोधन के अनुसार, अब नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे राज्य शासन के किसी भी विभाग में, किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक सेवारत था। परंतु शहीदों के परिजनों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस नीति में संशोधन कर यह विकल्प प्रदान किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल पर इस निर्णय को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा को लगातार शहीद परिवारों और उनके संगठनों से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें अनिवार्य रूप से पुलिस विभाग में नियुक्ति न देकर, अन्य विभागों में भी विकल्प मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रियता से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ। यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देने का कार्य है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी प्रमाण है।

खाद, बीज की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया समितियों का घेराव

विभिन्न मांगों के साथ सौंपा ज्ञापन।

कवर्धा (समय दर्शन)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिला एवं ब्लाक कांग्रेस कमेटी सहसपुर लोहारा द्वारा सेवा सहकारी समिति में व्याप्त खाद, बीज की भारी किल्लत और इसके चलते किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकासखण्ड सहसपुर लोहारा के अंतर्गत ग्राम बिड़ौरा, सूरजपुर, कुरुवा, जरहाटोला, स. लोहारा, सलिहा, बड़ौदा खुर्द, बिरनपुर सेवा सहकारी समितियों का घेराव कर अपनी मांगों के साथ स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

ब्लाक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक लचर व्यवस्था के चलते क्षेत्र में लगातार किसानों व सभी वर्गों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसना पड़ रहा है। इस संबंध में लंबे समय तक कोई सुनवाई नहीं होने के कारण लोगों

को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ रही है।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार की नीति प्रदेश चलाने की नहीं केवल भ्रष्टाचार शोषण और अपराधियों को संरक्षण देने तक की रह गई हैं। सरकार की उदासीनता के चलते ही प्रदेश अंधकार की ओर जा रहा है। खेती किसानी के इस सीजन में अन्नदाता किसानों को मांग के अनुरूप खाद, बीज नहीं मिल पा रहा है और वे बाजार से मंहगे दामों में खाद, बीज खरीदने मजबूर हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर किसानों को जल्द ही खाद, बीज उचित दामों पर उपलब्ध नहीं कराया गया तो चक्काजाम किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्य रूप भगवानसिंह पटेल, नेतराम जंघेल, चोवाराम साहू, भरत वर्मा, शरद बांगली, सौखी लाल साहू, रामाधार पटेल, संतोष पटेल, झूलाराम साहू, फत्ते साहू, शंभू पटेल, सुरेश पटेल, चन्द्रशेखर नागराज, चेतन पाली, ईश्वरी साहू, बाबूलाल पटेल, सेतराम श्रीवास, भागी पटेल, रामकुमार पटेल, रूपेश साहू, विजय ओगरे, जनकू पटेल, साहेब पटेल, रामाधार पटेल, जीवन झारिया, कमलेश पटेल, ताज मोहम्मद, खेला झरिया एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे पर अपनी त्वचा को दें कैलिफोर्निया आमंड्स का पोषण

रायपुर। वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे 2025 की थीम इस बार है त्वचा की सेहत के बिना संपूर्ण स्वास्थ्य संभव नहीं, जो इस बात पर ज़ोर देती है कि स्किन केयर सिर्फ क्रीम और लोशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत हमारे खान-पान से होती है। कैलिफोर्निया आमंड्स, जो विटामिन ई और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं, त्वचा को अंदर से पोषण देकर इसे स्वस्थ और दमकता बनाए रखने में मदद करते हैं। कैलिफ़ोर्निया आमंड्स 15 ज़रूरी पोषक तत्वों का बेहतरीन स्रोत हैं, जिनमें से कई त्वचा की रंगत और बनावट सुधारने में असरदार माने जाते हैं। इनमें मौजूद विटामिन ई और हेल्दी फैट्स त्वचा को उम्र के असर से बचाने वाले एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर होते हैं। रिसर्च से यह भी सामने आया है कि नियमित रूप से बादाम खाने से चेहरे की झुर्रियों को कम किया जा सकता है। यानी ब्यूटी रूटीन में बादाम को शामिल करना आसान और असरदार तरीका हो सकता है। वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे के मौके पर त्वचा की देखभाल के बारे में बात करते हुए स्किन एक्सपर्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉ. गीतिका मित्तल गुप्ता ने कहा, ''मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को याद दिलाती हूं कि असली स्किन हेल्थ शरीर के भीतर से शुरू होती है। अच्छी नींद, एक्टिव रहना और पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार, ये सब मिलकर त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। मेरी सबसे ज़रूरी सलाहों में से एक है रोज़ाना बादाम को डाइट में शामिल करना, चाहे स्नैक के रूप में या भोजन में मिलाकर। बादाम विटामिन ई, प्रोटीन, जिंक और कॉपर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं और यूवीबी किरणों से भी बचा सकते हैं।

सैमसंग ने भारत में नए गैलेक्सी फोल्डेबल फोन्सस के लिए प्री-रिज़र्व बुकिंग शुरू की

गुरुग्राम: सैमसंग 9 जुलाई को न्यूयॉर्क में अपनी अगली पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च करने जा रहा है। यह नई सीरीज़ एआई-पावर्ड इंटरफेस के साथ आएगी और इसमें एडवांस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्मार्टफोन का अनुभव पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और स्मार्ट हो जाएगा। आधिकारिक लॉन्च से पहले भारत में ग्राहक सिर्फ 2000 रूपए की टोकन राशि देकर इन नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को प्री-रिज़र्व कर सकते हैं। प्री-रिज़र्व करने वाले ग्राहकों को डिवाइस की खरीद पर 5999 रूपए तक के विशेष लाभ मिलेंगे और साथ ही उन्हें अर्ली डिलीवरी का भी फायदा मिलेगा। ग्राहक इन डिवाइसों को Samsung.com, सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर्स, Amazon.in, Flipkart.com और देशभर के प्रमुख रिटेल आउटलेट्स से प्री-रिज़र्व कर सकते हैं। सैमसंग ने इन डिवाइसों को उपयोगकर्ताओं की असल ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है—बेहतर परफॉर्मेंस, और भी तेज़ कैमरे और स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ। गैलेक्सी एआई सिर्फ डिवाइस की क्षमता तक सीमित नहीं है, यह इस बात पर आधारित है कि लोग टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़ते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाते हैं।

कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई ने आधुनिक रेडिएशन टेक्नोलॉजी के साथ कैंसर उपचार में सटीकता को बढ़ाया

रायपुर। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई ने आधुनिक रेडिक्सएक्ट0 ट्रीटमेंट डिलीवरी सिस्टम के साथ अपनी रेडिएशन थेरपी को अपग्रेड करते हुए अपनी कैंसर उपचार क्षमताओं में लक्षणीय उन्नति हासिल की है। यह आधुनिक टेक्नोलॉजी ऑन्कोलॉजी में हॉस्पिटल की लीडरशिप को मज़बूत करती है, कैंसर उपचार में उन्नत सटीकता, सुरक्षा और अनुकूलनशीलता लाते हुए मरीज़ों को मिलने वाले परिणामों में सुधार लाया है। रेडिक्सएक्ट0 ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में उपलब्ध व्यापक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मज़बूत किया है। अगली पीढ़ी की बुनियादी सुविधाओं, अंगों के अनुरूप सब-स्पेशलिटी निपुणताओं और वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क माने जाने वाले प्रोटोकॉल इन सभी का शक्तिशाली मिलाप इस सिस्टम में है। रेडिक्सएक्ट0 सिस्टम रेडिएशन थेरपी में एक लक्षणीय उन्नति है। स्वस्थ टिश्यू को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए सटीक उपचार देने की क्षमता इसमें है। बिल्ट-इन स्कैनर से लैस, यह सिस्टम पूरे उपचार के दौरान ट्यूमर सही स्थिति में है यह सुनिश्चित करने के लिए रियल-टाइम इमेजिंग देता है। यह सिस्टम बहुउपयोगी है, शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग प्रकार के कैंसर पर उपचार की क्षमता इसमें है। रेडिएशन के हायर डोस सुरक्षित तरीके से देकर, रेडिक्सएक्ट0 उपचार की सक्षमता को बढ़ता है। इसकी सिंक्रोनी टेक्नोलॉजी शारीरिक हरकतों के अनुकूल रहते हुए, सांस लेते हुए भी सटीकता को बनाए रखती है। यह दृष्टिकोण मरीज़ों को अधिक सुरक्षित और सक्षम उपचार अनुभव प्रदान करता है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में रेडिक्सएक्ट0 के लिए पूरक, भारत की एक सबसे बड़ी, प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी टेक्नोलॉजी की असेम्ब्ली है।

संक्षिप्त-खबर

पिरदा में विकासखण्ड स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव एवं साइकिल वितरण समारोह संपन्न

पिथौरा (समय दर्शन)। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पिरदा में विकास खण्ड स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 2025-26 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष पिथौरा श्रीमती उषा धृतलहरे, अध्यक्षता जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ब्रम्हानंद पटेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सीमा लोकेश नायक, जनपद सदस्य श्रीमती सुशीला अम्बु पटेल,

विधायक प्रतिनिधि हरप्रसाद पटेल, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य स्वप्निल तिवारी, विधायक निज सचिव नरेन्द्र बोरे, जनपद सदस्य पुरूषोत्तम धृतलहरे, दिनेश अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिमन्यु प्रधान, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति अध्यक्ष इंदल बरिहा, सरपंच ग्राम पंचायत पिरदा रंजन भोई, उपसरपंच मनोज पटेल, मिडिया प्रभारी हरिकेश भोई, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री त्रिलोचन नायक, पूर्व बीआरसी एफए. नन्द, प्राचार्य सेजेस पिरदा तरूण पटेल, पथरला सरपंच भरतलाल पटेल मंचासीन रहे। सभी अतिथियों का कर्मा दल के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं को पुस्तक प्रदाय किया गया। वहीं कक्षा नौवीं की 62 छात्राओं नि:शुल्क सरस्वती साईकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान किया गया। अतिथियों ने मेरिट छात्र-छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बी आर सी सी नरेस पटेल ने विज्ञप्ति में बताया कि इस दौरान सभी मेधावी छात्र छात्राएँ एवं विद्यालय के शिक्षक गण उपस्थित रहे।

ग्राम देवादा निवासी श्रीमती वेणुका चेलक द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण (छात्राओं को) दिया गया

पाटन। शासकीय प्रोन्नत पूर्व माध्यमिक शाला चिरपोटी जिला- दुर्ग छत्तीसगढ़ में 29 छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया , जो की आदेशानुसार एक माह तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया प्रशिक्षिका श्रीमती वेणुका चेलक (चीता जीत कुनेडो- (गोल्ड मेडलिस्ट) द्वारा 7 प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित थे विद्यालय के प्रधान पाठक श्री संतोष यादव जी, श्री कोमल साहू जी, श्रीमती मेनका बेलचंदन मैम, श्री प्रणव मंड्रिक जी,श्री संजय कुमार मानिकपुरी जी एवं शाला परिवार उपस्थित थे।

लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष का सर्किट हाउस रायपुर में किया जोशीला स्वागत, प्रदेश युवा अध्यक्ष सुरेश सिंगौर ने किया औपचारिक मुलाकात

पाटन। घनश्याम वर्मा (लोधी) जी प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज छत्तीसगढ़ ने आज सर्किट हाउस रायपुर में औपचारिक मुलाकात किया। जिसमें श्री सुरेश सिंगौर युवा प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज छत्तीसगढ़ मुलाकात के दौरान कबीरधाम जिला एवं राजनांदगांव खैरागढ़ दौरे के बारे में जानकारी दी। सामाजिक गतिविधि पर वरिष्ठ जनों, राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, सर्किल अध्यक्ष एवं युवा प्रदेश संगठन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा किया गया एवं आगामी बैठक दौरा के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया। उक्त मुलाकात में श्री के के सिंगौर जी प्रदेश महामंत्री लोधी समाज छत्तीसगढ़ एवं श्री अधीन जंघेल जी जिला अध्यक्ष लोधी समाज रायपुर और साथ में श्री दिलीप कौशिक जी भी उपस्थित रहे। यह जानकारी महासचिव दीपक जंघेल लोधी समाज रायपुर ने दी।

कलेक्टर से अछोली से भोरिंग मार्ग पर पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज के वाहनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग : अशवंत तुषार साहू

महासमुन्द (समय दर्शन)। भाजपा के सक्रिय सदस्य व किसान नेता अशवंत तुषार साहू ने कलेक्टर विनय लहंगे को ज्ञापन देकर कहा कि, पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज बेलटुकरी से गुमराह करके प्रस्ताव लिया गया है, जिसका विरोध ग्राम बेलटुकरी के सरपंच व पंचगण, सैकड़ो की संख्या में कलेक्ट्रेड ऑफिस का घेराव कर लगातार आंदोलन कर फैक्ट्री बंद करने की मांग किया था।

जब कि अछोली से और भोरिंग से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है और

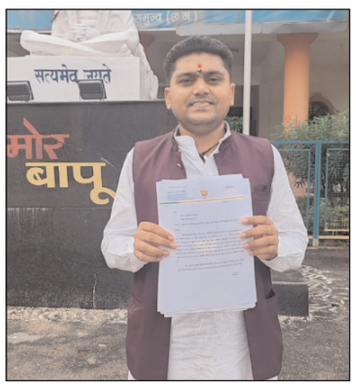

अछोली से भोरिंग रोड का उपयोग किया जा रहा है। जिससे स्कूली बच्चों लड़की, महिलाएं, आम नागरिकों को

खेत आने जाने में बहुत सारी तकलीफें का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त रोड पर सैकड़ो की संख्या में भारी वाहनों के आवागमन के कारण जगह-जगह रोड में गड्ढे हो गए हैं तथा रोड खराब हो चुका है। पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज बेलटुकरी के द्वारा सैकड़ो की संख्या में रोज हाईवा, ट्रक और अन्य बड़े वाहनों का आवागमन लगातार होता रहता है,,जिसके चलते यहां पर काम करने आए मजदूर का कोई अता-पता नहीं है कि कहां से आया है सभी का आधार कार्ड लेकर थाना में सूचना करना चाहिए, और उक्त कंपनी में काम करने के लिए बाहर से लोगों का, इन लोगों के कारण क्षेत्र में लगातार चोरी डकैती व लूटमार का शिकायत लगातार मिल रहा है। बाहर गांव व अन्य राज्य से आए हुए लोगों को देखकर ग्राम अछोली में डर का माहौल बना हुआ है।

शाम होते ही कंपनी के लेबर लोगों का रोड में मेले की तरह आने जाने का माहौल बना रहता है जिससे आवागमन बाधित होता है। इसके कारण रोड में चलने वाले आम नागरिक व स्कूली बच्चों, लड़की व महिलाएं को आने-जाने में डर महसूस करते हैं।इस संबंध में उच्च स्तरीय विभागीय जांच कर अवैध रूप से बना रहे पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज बेलटुकरी को बंद करें व अछोली से भोरिंग रोड मार्ग पर वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए । जनहित को देखते हुए अगर ग्रामीणों के साथ कुछ हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे।

आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन छिंदपाली में सम्पन्न

महासमुन्द (समय दर्शन)। जनसामान्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और आयुष पद्धतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयुष विभाग महासमुंद द्वारा संयुक्त संचालक आयुष डॉ.सुनील कुमार दास के निर्देशानुसार एवं महासमुन्द जिला आयुष अधिकारी डा.ज्योति गजभिये के मार्गदर्शन में स्वर्गीय श्रीमती सुलोचना दास जी की पुण्यतिथि में विकास खंडस्तरीय शिविर छिंदपाली में निशुल्क आयुष स्वास्थ्य एवं जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जिसमें श्रीमती रूपकुमारी चौधरी सांसद महासमुंद, जिला पंचायत अध्यक्ष महासमुंद श्रीमती मोंगरा पटेल, जनपद अध्यक्ष सराईपाली श्रीमती लक्ष्मी पटेल,महिला आयोग सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, जिला पंचायत सदस्य लोकनाथ बारी,श्रीमती कुमारी भास्कर जिला पंचायत सदस्य, डॉ प्रकाश पटेल प्रतिनिधि जनपद अध्यक्ष सराईपाली, संयुक्त संचालक आयुष डॉ.सुनील कुमार दास, जिला आयुष अधिकारी महासमुंद डा.ज्योति गजभिये,आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. गदाधर पंडा की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

मंच का संचालन डॉ. यशवंत चंद्राकर द्वारा किया गया।

आयुर्वेद में बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली संस्कार है, जिसे स्वर्णप्राशन संस्कार कहा जाता है। यह बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बुद्धि, स्मृति और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। 32 बच्चो मे स्वर्णप्राशन दिया गया।

वर्षा ऋतुचर्या विषय पर पामम्प्लेट वितरण किया गया एवं आहार परामर्श ऋतुचर्या के बारे में जानकारी दिया गया।

इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों ङ्क आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) के लाभों से अवगत कराया गया तथा 239 लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान किया गया ।

मुख्य आकर्षण

0 से 16 वर्ष के बच्चो के लिए स्वर्णप्राशन।

नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी,होम्योपैथिक दवाओं का वितरण।

योग एवं जीवनशैली पर कार्यशालाएं।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर ङ्क बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन आदि।

इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी, स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

खाद बीज की किल्लत को लेकर काँग्रेस ने सोसायटी का किया घेराव

■ किसानों के हित मे काँग्रेस का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

बसना (समय दर्शन)। सहकारी समिति भुकेल में ब्लाक कांग्रेस बसना द्वारा किसानों के हित में प्रदेश में खाद एवं बीज की किल्लत को दूर करने सोसायटी का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया गया।

जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रभारी एवं प्रदेश किसान कांग्रेस महामंत्री राजेश जैन, प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष दाऊलाल चन्द्राकर , वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनजीत सिंह सलूजा, तौकीर दानी इश्तियाक खेरानी, मोक्ष प्रधान जिला पंचायत सदस्य, शिव बघेल, श्रीमती मंदाकिनी साहू, यासीब धनानी, रज्जू छाबड़ा, प्रकाश जैन, तनुजा साहु, अध्यक्ष महिला कांग्रेस ग्रामीण नसरीन बानो, अध्यक्ष महिला कांग्रेस शहर मनोज गहरवाल, पार्षद शिव नायक , पार्षद रमेश दास, कैलाश प्रधान, महेंद्र नायक, राजकुमार कालु, प्यारेलाल साहू, केशव पटेल, राधेराम नंद ,सेतकुमार डड़सेना, राधेश्याम नायक, मोहित कश्यप, सी डी बघेल, उत्तर कुमार पारेश्वर, मनोज प्रधान, प्रकाश दास, करुण दाऊ,रियाज भाई ,गोकुल पारेश्वर, ननकी भाई सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन बसना तहसीलदार के के साहु को सौंपा गया।

ग्राम बेलतरा पंचायत की अनूठी पहल,गांव में खुले में शराब, गांजा, ताश, डिस्पोजल, सार्वजनिक स्थान में मास खाने पर लगेगा अर्थदंड

■ सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम राशि

जीवन साहू/समय दर्शन

साजा (समय दर्शन)। साजा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलतरा में अवैध शराब एवम गांजा बिक्री के संबंध में गांव में आवश्यक बैठक रखा गया, जिसमें गांव के वरिष्ठ नागरिक, युवाओं,महिला समूह,मितानिन समूह,सरपंच, उपसरपंच,पंचगण,एवं जनप्रतिनिधि के साथ गांव के सभी वर्गों के लोग अधिक संख्या में शामिल हुए और सभी ने मिलकर शराब बंदी एवम गांजा, ताश, को बंद करने के संकल्प के साथ सर्व सम्मति से नियम पारित कर गांव स्तर पर दण्ड विधान बनाया गया। शराब व गांजा बेचते पाए जाने पर 51000 रुपए दण्ड रखा गया।खरीदने वाले को 21000 रुपए दण्ड रखा गया है। बताने वाले को 15000 रुपए इनाम रखा गया। स्कूल, तालाब, गौठान शासकीय भवन, तालाब किनारे मंदिर के पास खुला में शराब पीने पर दंड 11000 रुपए और बताने वाले को ?5000 इनाम रखा गया। गांव में शराब पीकर बहस बाजी करने गाली गलौज करने वाले के ऊपर ?5000 दंड रखा गया। गांव में मटन मछली बकरा बनाकर कोई भी सार्वजनिक स्थान में नहीं खाना है ।अगर खाते पाए जाते हैं तो ?2000 दंड और बताने वाले को ?1000 इनाम रखा गया है। गांव में छठी एवं शादी समारोह पर खुले में शराब पिलाने पर ?11000 दंड रखा गया है।

गांव में खुला डिस्पोजल बेचने वाले के ऊपर ?5000 दंड और बताने वाले को ?2000 इनाम (केवल किसी कोल्ड ड्रिंक के साथ डिस्पोजल देने की अनुमति होगी खुले में नहीं देना है)। गांव में ताश खेलने के ऊपर प्रतिबंध है अगर ताश खेलते पाए जाते हैं तो प्रति व्यक्ति ?2000 दंड और बताने वाले को ?1000 इनाम रखा गया है।

जिसमें गांव के सरपंच भारती मुकेश टंडन, उपसरपंच सगन राम साहू, एवम् सभी पंचगण सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष नेतराम साहू , पूर्व सरपंच उमेंद साहू, मितानिन संघ अध्यक्ष सुमन साहू , सक्रिय महिला समूह काजल मानिकपुरी, एवम् समस्त महिला समूह अध्यक्ष और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहें।

ट्रिपल इंजन सरकार में किसान, मजदूर सहित हर वर्ग त्रस्त...अशोक साहू

पाटन विधानसभा के डंगनिया सोसायटी में किसानों के साथ विधायक प्रतिनिधि ने सौंपा ज्ञापन!

पाटन (समय दर्शन)। प्रदेश, जिला, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निर्देश में प्रदेश के सभी सेवा सहकारी समितियों में खाद,बीज उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधायक प्रतिनिधि पूर्व जिप उपाध्यक्ष अशोक साहू ने किसानों के साथ सेवा सहकारी समिति डंगनिया में ज्ञापन सौंपा।उन्होंने ट्रिपल इंजन सरकार को पूरी तरह असफल होने का आरोप लगाया।आज किसान खाद के लिए दर दर ठोकरें खा रहे है,बिजली कटौती से किसान एवं आम जनता त्रस्त हैं। आषाढ़ में मानसूनी बादल भी दगा दे रही है।अमानक बीज उपलब्ध करा के कृषि विभाग चैन की नींद सो गई है।शासन,प्रशासन को सुध लेने की फुर्सद नहीं है। उन्होंने बताया कि ट्रिपल इंजन सरकार के कुशासन का दंश किसान,मजदूर,युवा, महिलाएं,अधिकारी,कर्मचारी,शिक्षक सहित सभी वर्ग झेल रहे हैं।कांग्रेस पार्टी एवं छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर जुल्म,अन्याय,अत्याचार,हिंसा,अनैतिक कार्यों का पुर जोर विरोध प्रदर्शन कर रही है।आगे भी जनहित आवाजों को बुलंद हम सब मिलकर करते रहेंगे। इस दौरान किशोर साहू,डॉ के के साहू,डोनेश्वर मढ़रिया,डा हेमंत साहू,शिवकुमार सेन,ज्ञानलाल वर्मा,गजेंद्र साहू,कृष्णकुमार साहू,पवन साहू,द्वारिका साहू,बीरेंद्र देवांगन,हुमन साहू,हरिश्चंद्र,देवेंद्र साहू,मुनी साहू,टेमन ठाकुर आदि किसान उपस्थित थे।

आपातकाल की स्याह छाया और लोकतंत्र की पुकार, 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा का मॉक पार्लियामेंट : विधायक डॉ. संपत अग्रवाल

रायपुर (समय दर्शन)। 1975 की वो रात, जब लोकतंत्र की लौ पर अंधकार की चादर डाल दी गई । आज, ठीक पचास वर्षों बाद, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने इस ऐतिहासिक त्रासदी की पुनरावृत्ति को स्मरण करने एवं युवा पीढ़ी को लोकतंत्र की नाजुकता से परिचित कराने हेतु भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 2 जुलाई को 'मॉक पार्लियामेंट' आयोजित करने की घोषणा की है। यह आयोजन रायपुर स्थित अग्रसेन धाम में संपन्न होगा। राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी,बसना विधायक डॉ संपत अग्रवाल, आरंग विधायक खुशवंत सिंह साहेब ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले मॉक पार्लियामेंट के पोस्टर का विमोचन किया । जिसमें भाजपा के युवा नेता सहित प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज सबसे काली तारीख़ थी। उस रात सिर्फ अधिकार नहीं छीने गए, बल्कि जनभावनाओं को अनसुना कर कांग्रेस की सत्ता की चाह में देश को बंदी बना दिया गया। इस 'मॉक

पार्लियामेंट' का उद्देश्य इतिहास को पुन: मंचित करना है, ताकि आज की पीढ़ी महसूस कर सके कि लोकतंत्र कोई स्थायी उपहार नहीं, बल्कि सतत रक्षा की मांग करता है।

मुख्य विषयवस्तु:

प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और उत्पीड़न

संविधान संशोधन और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना

जनमत की अनदेखी और राजकीय दमन

विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कांग्रेस द्वारा लागू आपातकाल की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि व्यक्तिगत सत्ता-लिप्सा के लिए देश को झोंक देने वाली मानसिकता को उजागर करना आवश्यक है। लाखों नागरिकों की गिरफ्तारी, पत्रकारों की आवाज़ को कुचलना और विपक्षी विचारों पर प्रहार , यह सब लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध था।

उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रहित में आयोजित प्रयास है जो जनता को याद दिलाने हेतु कि लोकतंत्र को सजग रहकर ही जीवित रखा जा सकता है।

स्वामित्वधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित खड़तकर द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ग्राम छाटा, पोस्ट देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) 491111 से मुद्रित कर बी-4, प्रेस काम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, दुर्ग छ.ग. 491001 से प्रकाशित। संपादक :- रोहित खड़तकर, समाचार संपादक : दामोदर राव, फोन नं.-0788-4051213, मो. 9827104452, रायपुर कार्यालय:-0771-4218364, ईमेल - samay.darshan191@gmail.com पं. क्र. CHHHIN/2011/41517 डाक पंजीयन क्रमांक छ.ग./दुर्ग/61/2024-26